04 - समृद्धि के उजालों के बावजूद धनाढ्यों का पलायन क्यों ?

05 - याद आते हैं कुआं, ताल-पोखर वाले दिन

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 9 नवंबर, 2024

06 - अनदेखी : जालियां चोरी होने के बाद नपा ने नहीं किये दूसरे प्रयास...

07- भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-70 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

झारखंड में योगी के 'बंटोगे तो कटोगे' नारे का कितना होगा असर ?

मृत्युंजय दीक्षित

बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ से त्रस्त झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2024 का विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। समृद्ध खनिज भंडार वाले इस राज्य की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में विगत वर्षों में बड़ा असुंतलन व्याप्त हो गया है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को ही अपना चुनावी विषय बनाया है। साथ ही परिवारवाद व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के काले कारनामे भी हवा में तैर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा परिणाम आ जाने के बाद देश का राजनैतिक वातावरण एकदम से बदल गया। झारखंड और महाराष्ट्र सहित जहां-जहां विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं सभी जगह एनडीए और इंडी दोनों गठबंधनों का गणित बदल गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा 'बंटेंगे तो कटेंगे' हरियाणा से होता हुआ बांग्लादेश और कनाडा तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नये नारे का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसके कारण जाति के आधार पर हिंदू समाज को विभाजित कर सत्ता हथियाने वाले विपक्षी दलों के चेहरे पर तनाव व्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नये नारे की लोकप्रियता इसी बात से समझी जा सकती है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक उनके नारे के साथ पोस्टर लगाये जा रहे हैं। झारखंड में 10 बुलडोजरों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया।

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी आक्रामकता के साथ हिंदुत्व की बात करते हुए चुनाव प्रचार कर ही है जिसका नेतृत्व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा व केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता जो अपने राज्य असम में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं ने अपनी चुनावी जनसभाओं में इसे बहुत ही आक्रामक ढंग से उठाया है और वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह चुनाव किसी विधायक को चुनने का नहीं है अपितु अपना अस्तित्व बचाने का है। जब हम हिंदू बचे रहेंगे तभी तो आपना विधायक और सांसद चुन सकेंगे, अपनी सरकार चुन सकेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता का कहना है कि देश के हर कोने में जहां- जहां बाबर बसे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढकर देश से भगाया जाएगा।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माटी, रोटी और बेटी बचाने का संकल्प लिया है और समाज की चार जातियों महिला, किसान, युवा और गरीब जनता के लिए वादों का पिटारा खोलते हुए उत्तराखंड व गुजरात की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निश्चय व्यक्त किया है। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगे। आज झारखंड राज्य की जो दयनीय स्थिति हो गई है उसके पीछे हेमंत सोरेन सरकार का परिवारवाद, उससे पनपा अथाह भ्रष्टाचार और फिर मुस्लिम तुष्टिकरण ही तीन प्रमुख कारण हैं। राज्य का हिंदू व आदिवासी समुदाय तो ईसाई मतांतरण व मुस्लिम लव जिहाद, लैंड जिहाद के जाल में फंसकर अल्पमत में आता जा रहा है। राज्य में मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण हालात यह हो गये हैं कि झारखंड में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में रविवार का अवकाश ही समाप्त कर दिया गया और मुस्लिम बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों में हिंदू बच्चों से कहा गया कि आप हाथ जोड़ कर प्रार्थना मत करिये, यहां पर हाथ जोड़ने वाली परम्परा हटा दी गई हैं क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। देश के कुछ अन्य हिस्सों की तरह ही झारखंड में भी हिंदू पर्वों पर मुसलमानों द्वारा हमलों की बाढ़ सी आ जाती है। झारखंड की जनता 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह न देख पाए इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जानबूझकर कई जिलों में बिजली सप्लाई तक बाधित कर दी गई थी।

अब झारखण्ड की राजनीति बदलने के लिए हिमंता और शिवराज के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभाओं का आरम्भ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की रैलियों ने वातावरण में जोश भर दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि झारखण्ड विधानसभा चुनावों में इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ ही रोटी-बेटी और माटी के साथ-साथ नोटों के पहाड़ का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया जाएगा। झारखंड की जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और आदिवासियों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन पर जमकर प्रहार किया। हेमंत सोरेन पर अपने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लग चुका है तथा बीजेपी की ओर से उनका नामांकन रद्द करने तक की मांग गई थी।

झारखंड में कमल खिलाने में एक और व्यक्ति जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी वो हैं उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल फुल फॉर्म में हैं। बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक हिंदुओं के मंदिरों व पर्वों पर हो रहे हमलों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समग्रता के साथ अपील कर रहे हैं कि अपनी ताकत का अनुभव करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कांग्रेस व विपक्ष यही काम करती आ रही है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या आदि को बुला रहे हैं जो एक दिन आपको घर के अन्दर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए नेक रहिए। मैं तो कहता हूं कि जब भी बंटे हैं निर्ममता से कटे हैं।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के नये नारे का ही प्रभाव है कि अब बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक का हिंदू पूरी एकजुटता के साथ सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहा है। योगी जी के नारों से विपक्षी खेमा हताश है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। विपक्षी खेमे में की हालत यह है कि योगी जी बोल झारखंड में रहे थे किंतु उन पर पलटवार महाराष्ट्र और लखनऊ से हो रहा था। यह भी माना जा रहा है इस नये नारे से बीजेपी ने कांग्रेस के जातिवाद की राजनीति का तोड़ भी खोज लिया है जिसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर निर्माण की बात करते हुए भावुक होकर कांग्रेस व विपक्ष पर हमलावार होते हैं। योगी जी अपनी स्पष्टवादिता के कारण ही लोकप्रिय हैं, दूसरे चुनावी राज्य महाराष्ट्र में भी उनकी 22 रैलियां निर्धारित हैं जिन्हें बढ़ाने की मांग की जा रही है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संचालन के प्रयास बढ़ाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

● मध्यप्रदेश में 1. 29 लाख विद्यार्थियों ने लिया बहुविषयक अध्ययन का लाभ ● कृषि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की रूचि बढ़ी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत प्रदेश में अनेक नवाचार हुए हैं। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी उच्च शिक्षा के जुड़े नवाचार करें। अच्छे प्रयोगों का सदैव स्वागत है। शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के प्रयास हों। पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सक्षम युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे बड़ी गारंटी मानते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान भी हुए हैं। इस नीति में युवाओं को ज्ञानवान और अनेक विषयों में पारंगत बनाने की रणनीति बनाई गई है।

बहुविषयक शिक्षा में आगे मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वविद्यालयों द्वारा बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने और रोजगार के लिए उपयोगी पाठ्यक्रमों के संचालन की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर कुलगुरूओं और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। बताया गया कि विद्यार्थियों को बहुविषयक दृष्टिकोण (मल्टी डिस्पलीनरी एप्रोच) के माध्यम से अन्य विषयों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के निरंतर प्रयास किए जाएं। वर्तमान में प्रदेश के लगभग एक लाख विद्यार्थी वाणिज्य के साथ कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कला संकाय के 18 हजार विद्यार्थी वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। मध्यप्रदेश में विज्ञान संकाय के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 11 हजार है, जिन्होंने कला और वाणिज्य विषय का चयन किया है। इस तरह एक लाख 29 हजार विद्यार्थियों ने बहुविषयक शिक्षा का लाभ लिया है।

विद्यार्थी ले रहे खेती किसानी की शिक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक बिन्दुओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्नातक स्तर पर कृषि जैसे विषय के अध्ययन के प्रावधान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। सात विश्वविद्यालयों और 18 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में बी.एससी. कृषि पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है। इन पाठ्यक्रमों का लाभ 1189 विद्यार्थी ले रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में सर्वाधिक 240 विद्यार्थी खेती किसानी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में पायलेट ट्रेनिंग के कोर्स के संचालन और एविएशन के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पांच विश्वविद्यालयों ने पहल की है। निश्चित ही युवाओं को इन पाठ्यक्रमों का रोजगार की दृष्टि से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

इन्क्यूबेशन केन्द्रों की सक्रिय भूमिका, स्टार्ट अप्स को पूर्ण प्रोत्साहन

प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 47 इन्क्यूबेशन सेन्टर प्रारंभ किए गए हैं। इनमें शासकीय विश्वविद्यालय में 16, निजी विश्वविद्यालय में 12 एवं शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में 19 इन्क्यूबेशन केंद्र संचालित हैं। देवी अहिल्या विश्व विद्यालय इंदौर को केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पांच करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर इन्क्यूबेशन सेंटर को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल कम्युनिटी इन्नोवेशन सेंटर के लिए 2.5 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के लिए 13.4 लाख रूपए स्वीकृत हुए हैं। प्रदेश के 2 निजी विश्वविद्यालयों में भी अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इनमें रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल और लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (एलएनसीटी) भोपाल शामिल हैं। इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सीएम डॉ. यादव आज इंदौर में देंगे सौगातें

1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगी 1250 रूपये की नवम्बर माह की किश्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवम्बर को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना, गैस रीफिल एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 करोड़ 10 लाख हितग्राहियों के खातों में 1961 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। इसमें 1 करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1573 करोड़ रूपये, 26 लाख बहनों के खातों में सिलेंडर रीफिल की राशि 55 करोड़ रूपये और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की जायेगी। नेहरु स्टेडियम में 5 हजार से अधिक बालिकाओं के द्वारा तलवार चलाने के वर्ल्ड रेकार्ड बनाने का कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर के ढक्कन वाला कुँआ स्थित ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लेपटॉप, मोट्रेट ट्राईसिकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री आईटीसी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

सुप्रभात

औरों का मन पढ़ते-पढ़ते अपना ही मन भूल गए
सच बोलूं तो बचपन में ही अपना बचपन भूल गए
बारिश का पानी था लेकिन कागज वाली नाव नहीं
जख्म हृदय पर अनगिन गहरे लेकिन कोई घाव नहीं
यौवन की दहलीज पे चढ़ते ही हम दर्पण भूल गए
इन हाथों की कई लकीरें खुरच खुरच के बनाई है
छोटी सी पहचान मेरी जो अपने दम पर पाई है
जबसे समझ हुई जीवन की सबसे अनबन भूल गए
जो कुछ था किस्मत में मेरी सब मैंने स्वीकारा है
लेकिन मेरी जिद के आगे कई बार वह हारा है
परपीड़ा के चिंतन में हम अपनी उलझन भूल गए।

- प्रियंका राय 'नंदिनी'

चीता कॉरिडोर पर मिलकर काम करेंगे एमपी-राजस्थान

दोनों राज्यों में चीतों की बसाहट से बढ़ेगा टूरिज्म, जॉइंट कमेटी देगी सुझाव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा गांधी सागर में चीतों की बसाहट का फैसला लेने के बाद अब राजस्थान और एमपी सरकार चीता कॉरिडोर पर जॉइंट वर्किंग पर फोकस करेगी। कूनो अभयारण्य में चीतों की बसाहट में सफलता मिली है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के निर्देश पर चीतों को अंतरराज्यीय भ्रमण के लिए छोड़ने और टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसी के मद्देनजर एमपी और राजस्थान सरकार एक साथ मिलकर चीता कॉरिडोर पर काम करेंगी। सरकार द्वारा इसके लिए बनाई गई कमेटी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के एरिया में एमपी और राजस्थान से जुड़े क्षेत्रों की विजिट करेगी। इन क्षेत्रों में कूनो और रणथंभोर आदि शामिल हैं। इसमें दोनों राज्यों के हिसाब से जॉइंट टूरिज्म रूट की संभावनाओं को तलाशने का काम किया जाएगा। यह समिति हर तीन माह में एमपी और राजस्थान सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

यह काम भी करेगी जॉइंट कमेटी

मोहन सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी एमपी-राजस्थान में आइडेंटिफाईड लोकेशन पर चीता कॉरिडोर के विकास के सुझाव देगी। इसके साथ ही कॉरिडोर प्रबंधन के अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच रूह भी किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा अधिकारी और फ्रंट-लाइन कर्मचारी चीतों की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। भविष्य में माइग्रेशन की स्थिति में एरिया डेवलपमेंट और प्री-ओगमेंटेशन बेस की अनुशंसा कमेटी द्वारा की जाएगी।

पीएम का नया नारा, 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे'

● कहा-कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी अब जातियों को लड़ा रही है ● कहा-महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं, न ब्रेक, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट में भाषण में मोदी ने महा विकास अघाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे। इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ साजिश है। मोदी ने ये भी कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं, न ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। चारों तरफ से अलग-अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजित गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, यहां के लोगों ने दिल खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया।

● कांग्रेस दलितों-पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती

कांग्रेस की तरफ से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। अंबेडकर ने कोशिश की, वंचितों को आरक्षण मिले लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। बाबा साहेब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए। नेहरू के बाद इंदिरा जी आईं। उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ यही माहौल बनाए रखा।

● कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा

कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्यधारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में अंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया। देश में दो संविधान रहते थे, कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। इन्होंने अलगावदियों को संरक्षण दिया।

एमवीए ने पहले सरकार, फिर जनता को लूटा

हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग लोगों को लूटने आए हैं। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले आते हैं तो हर योजना बंद कर देते हैं। आपने महाविकास अघाड़ी के धोखे से बनी सरकार के ढाई साल देखे हैं। इन्होंने पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा। महायुति का वचननामा (मैनिफेस्टो) विकसित भारत का आधार बनेगा। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के लिए हमारी बहन-बेटियों का जीवन आसान बनाना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र की हर महिला को अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये नारी शक्ति को सशक्त नहीं देख सकते। ये महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं, कैसी-कैसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस में 25000 बेटियों की भर्ती से महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा। उन्हें सुरक्षा मिलेगी।

370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

● विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की, मार्शलों ने पहले गिराया, फिर बाहर निकाला

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया। जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। खुर्शीद अहमद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 30 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 9 नवंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

शिवराज ने जलाई भाजपा में 'दीपक' की लौ

अम्बुज माहेश्वरी

पुराने साथी को पार्टी में वापिस लाने पूर्व मुख्यमंत्री ने बनवाई सहमति

भोपाल। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का दामन थामते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने जिस शिवराज को अपना बड़ा भाई मानने से इंकार करते हुए उनकी सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे उन्होंने ही दीपक जोशी की भाजपा में वापसी का रास्ता तैयार कर पार्टी में सहमति बनवाई। भाजपा में शामिल कराने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीटर पर भी प्रिय भाई के संबोधन के साथ उन्हें बधाई दी। विधानसभा चुनाव हारने के पहले तक दीपक जोशी न केवल बीजेपी के खिलाफ लगातार हमला कर रहे थे बल्कि प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। हार के बाद से विचलित श्री जोशी भाजपा में शामिल होना चाहते थे लेकिन उनके बयानों के कारण एंट्री होल्ड हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के कई सीनियर नेता दीपक जोशी की भाजपा में वापसी पर सहमत नहीं थे लेकिन शिवराज सिंह चौहान द्वारा तय कर लेने के बाद पार्टी में सहमति बन गई। राजनीतिक हल्कों में चर्चा है कि मध्यप्रदेश की राजनीति के संत स्व कैलाश जोशी के दीपक की लौ भाजपा में शिवराज ने जलाई है।

दीपक जोशी ने कहा मैंने गलती की थी – भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा मेरा घर है। मैं जनसंघ के जमाने वाले परिवार से हूं। मेरे पिताजी, मैंने और शिवराज जी ने साथ में काम किया है। पगडंडी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर इसी पार्टी ने कराया है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि मैंने गलती की थी। उस गलती को ठीक करके अब मैं अपनी पार्टी में वापस आ गया हूं।

सरताज को भी शिवराज ही वापिस लाए थे – 2018 के चुनाव में टिकट कट जाने से नाराज होकर कांग्रेस के टिकट पर होशंगाबाद से चुनाव लड़े और हारे स्व सरताज सिंह को दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह ही भाजपा में वापिस लाए थे। उनकी वापसी पर शिवराज सिंह ने कहा था कि आप कहां दुष्टों में फंस गए थे। तब स्व सरताज सिंह ने कहा था बीजेपी मेरी मातृ संस्था है,पार्टी में कभी मन मुटाव होता रहता हैं, मगर अब सब ठीक है।

बुरा बोलने पर भी बुरा नहीं माने शिवराज – विगत वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के लिए कई मामलों में चुनौती बनते नजर आए वरिष्ठ नेता सत्य नारायण सत्तन, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, कृष्ण मुरारी मोघे, कुसुम मेहदेले, रघुनंदन शर्मा, कैलाश चावला को अलग अलग मौकों पर साधने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। चार बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह को पार्टी के भीतर या बाहर कई बार भला बुरा कह देने वाले कई नेताओं को भी मौका पड़ने पर शिवराज ने उनका साथ देकर पार्टी में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

चार साल में शिवराज-शेजवार की बढ़ी दूरियां

धर्म के रिश्ते में जीजा-साले लगने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री की दूरियां पिछले चार साल में अधिक बढ़ गई हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने शिवराज सिंह और तब पटवा सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे डॉ गौरीशंकर शेजवार के शुरुआती राजनीतिक रिश्तों में खूब तल्खियत भी रही तो 2013 से 18 तक शिवराज सरकार में वन मंत्री रहते वे कई बार संकट मोचक की तरह नजर भी आए। 2020 में सिंधिया समर्थक डॉ प्रभुराम चौधरी का भाजपा में शामिल होना और इसके बाद डॉ शेजवार के जन्मदिन पर राजा, घोड़े और जादूगर की कहानी का राजनीतिक रूप से सामने आना इस रिश्ते पर भारी पड़ गया। सूत्र बताते हैं कि दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि अब आपसी संवाद भी नहीं होता है।

महाकाल मंदिर सुरक्षा के लिए 500 होमगार्ड की तैनाती जल्द

उज्जैन (नप्र)। 19 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। अब जल्द ही इस पर अमल होने वाला है। दो दिन पहले भोपाल में हुई बैठक में महाकाल मंदिर में जल्द ही 500 जवानों की तैनाती पर मुहर लग गई है। खास बात यह है कि इन 500 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए उज्जैन जिले के युवाओं को मौका मिलेगा, साथ ही 500 गार्डों की सैलरी का भार प्रदेश पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा खर्च महाकाल मंदिर समिति उठाएगी।

वित्त विभाग की औपचारिक अनुमति बाकी – धार्मिक न्यास विभाग के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड को सौंपने की घोषणा की थी। अब इसको लेकर हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। होमगार्ड के डीजीपी अरविंद कुमार ने बताया कि सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग की औपचारिक अनुमति मिलते ही महाकाल मंदिर में होमगार्ड के सैनिकों की तैनाती की जाएगी। प्रस्ताव दिया गया है कि 500 गार्डों की भर्ती के लिए उज्जैन जिले के युवाओं को अवसर मिलेगा, हालांकि अभी इसके आदेश होना बाकी है। सैनिकों की सैलरी का खर्च महाकाल मंदिर समिति उठाएगी। ये 500 गार्ड डिप्टी कमांडेंट, कंपनी कमांड और जिला सेनानी के कमांड में रहेंगे।होमगार्ड डीआईजी मनीष अग्रवाल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के अंडर 500 जवान तैनात होंगे। प्रस्ताव में उज्जैन जिले के युवाओं को अवसर देने की बात की गई है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा, और इसमें परीक्षा कैसे होगी, यह सब देखना बाकी है।

फिलहाल सुरक्षा निजी क्रिस्टल कम्पनी के हाथों में – महाकाल मंदिर और महालोक की सुरक्षा व्यवस्था मुंबई की निजी कंपनी क्रिस्टल सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार करने, दर्शन कराने के एवज में पैसे मांगने के आरोप कई बार लगे हैं। महाकाल मंदिर और महालोक की सुरक्षा में होमगार्ड की तीन कंपनियां लगाई जाएंगी। इन तीन कंपनियों में 492 जवानों की तैनाती होगी, और उनकी ड्यूटी आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में लगाई जाएगी।

भोपाल में सीएम यादव बोले

कई घुसपैठियों को पाल-पोस रही कांग्रेस पायलट के बयान पर कहा- वोट बैंक के डर से बांग्लादेश की घटनाओं पर कांग्रेस चुप

भोपाल (नप्र)। भोपाल में शुक्रवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के बयान पर पलटवार किया है। झारखंड प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सीएम ने कहा - जहां कांग्रेस के लोग रहते हैं धर्मों के आधार पर बांटते हैं। देश की आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस है। देश में कुशासन के कारण अगर अतीत की घटनाएं देश को सहन करना पड़ी हैं तो उसमें कांग्रेस की भूमिका है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पर ही आरोप आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती।

दरअसल गुरुवार को भोपाल पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं के बयान 'बंटेंगे तो कटेंगे' पर कहा था कि- बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे।

देश में कई घुसपैठियों को कांग्रेस पाल-पोस रही – सीएम ने कहा- भाजपा के साथ बढ़िए देश के साथ रहिए, सनातन की जड़ों के साथ जुडिए। हमारे देश में कई घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल पोस रही है। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? क्योंकि उसे वोट बैंक का खतरा लगता है। किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को टॉर्चर करना ये कांग्रेस की नीति ही मूलतः गलत है। भाजपा के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने सबका साथ सबका विकास जो भावना प्रधानमंत्री जी की है उसमें सबका विकास निहित है।

सीएम बोले- राहुल गांधी नकली गांधी – नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है' वाले बयान पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में कहा- जो जनतंत्र को खत्म करने लगे उनकी दादी का इतिहास है आपातकाल किसने लगाया? वो किस पर आरोप लगाएंगे ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करेंगे तो जनता हिसाब चुकता करेगी।

पायलट के बयान पर सीएम ने पलटवार किया – विजयपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सचिन पायलट ने भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा था- मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे। मैंने कहा कि हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए।

बैलगाड़ी से घूम रहे विदेशी, रात में गा रहे भजन

पचमढ़ी के पर्यटकों का होम स्टे बना छिंदवाड़ा का सावरवानी, 300 विदेशी सैलानी आ चुके

- होम स्टे को ऐसे बनाया गया है कि पर्यटक ग्रामीण कल्चर को जान सकें।
- पर्यटकों का फूल देकर स्वागत किया जाता है।
- लोग सुविधाओं के साथ कच्चे घरों में रहते हैं। ग्रामीण जीवन को अनुभव करते हैं।

छिंदवाड़ा (नप्र)। 'प्रकृति की खूबसूरत वादियां, मिट्टी के घर, सूर्योदय, आंख खुलने पर पक्षियों की चहचहाहट, ताजी हवा, शुद्ध भोजन....' अब शहरी लोगों के लिए यह सब दुर्लभ है। यही वजह है कि छिंदवाड़ा जिले का सावरवानी गांव अन्य राज्यों के सैलानियों समेत विदेशियों को भी भा रहा है। अब तक 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य को जीने आ चुके हैं। शनिवार-रविवार और छुट्टियों वाले दिनों में बुकिंग ज्यादा रहती है। महाराष्ट्र-दिल्ली से टूरिस्ट ज्यादा आते हैं।

बैलगाड़ी पर घूमना, गायों का दूध निकालना, उन्हें खिलाना, छोटे-मोटे कृषि कार्यों में भाग लेना और पास के मोनाखेड़ी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करना, ढोलक-मंचीरे के साथ भजन और आदिवासी कर्मा नृत्य मंडलियों की उपलब्धता जैसे अनुभव लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खासतौर पर पचमढ़ी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यह पसंदीदा होम स्टे बन चुका है। यहां लोग सुविधाओं के साथ कच्चे घरों में रहते हैं। ग्रामीण जीवन को अनुभव करते हैं।

ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जी व फल के साथ स्थानीय भोजन करते हैं। यह कल्चर बहुत रास आ रहा है। कई लोग तो दो से तीन बार आ चुके हैं। घूमने आए कुछ पर्यटक कहते हैं कि बच्चे यहां आकर मोबाइल फोन से दूर हो जाते हैं। हमें यह देखकर सुकून मिलता है। वरना हमारे शहर के घरों में तो वे दिन भर टीवी और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। हमसे बात तक नहीं करते। स्टे बनने से आसपास के तीन गांवों की महिलाओं और ग्रामीणों को भी घर में ही रोजगार मिल गया है। आज हम सवारवानी गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर केंद्र सरकार ने जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी में पुरस्कार दिला।

क्रिसमस तक के लिए अभी से पूरे होम स्टे बुक – ग्रामीण जीवन और कल्चर को देखने आने वाले होम-स्टे के लिए मिट्टी के घर (मड हाउस) बने हैं। इनका किराया तीन हजार रूपए प्रतिदिन है, जिसमें दोनों वक्त का भोजन एवं चाय निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। शाम को गांव के लोकल ट्राइबल ग्रुप शैला लोक नृत्य से पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। हालांकि अब तक 7 होम स्टे ही बने हैं, प्रशासन का दावा है कि जल्द इनकी संख्या 67 होने वाली है। पर्यटकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के कारण भी लोगों में बेहद उत्साह है।

छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर और पचमढ़ी हिल स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में सावरवानी गांव बसा है। गांव की बच्चियां यहां गाइड और संचालक के रूप में कार्य कर रहीं है। तीन गांव की सावरवानी ग्राम पंचायत में बने होम स्टे से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। सावरवानी गांव के पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश यदुवंशी ने बताया कि पिछले दिनों गुजरात के 6 व्यापारी एक दिन के लिए आए थे, उन्हें इतना अच्छा लगा कि 7 दिन यहीं रहे। हर महीने 50-60 टूरिस्ट आ रहे हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के लिए अभी से पूरे होम स्टे बुक हैं।

पर्यटक बोले- बच्चे मोबाइल-टीवी से दूर रहते हैं –नागपुर से 15 दिन में दूसरी बार आए डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि हमारे बच्चे के जन्म दिन मनाने के लिए 12 अक्टूबर का यहां आए थे। यह जगह इतनी पसंद आई कि हमने इस बार दूसरी जगह जाने का सोचा तक नहीं। यहां पूरा नैसर्गिक वातावरण है मिट्टी और लकड़ियों का देसी घर है, स्वच्छता है। यहां भोजन में बाड़ी में उगी जैविक सब्जियां और मक्का-बाजरा, रागी सहित मोटे अनाज की रोटियां दी जाती हैं। यहां के भोजन से पेट खराब नहीं होता। मैं पिछली बार तामिया आया था तब इस होम स्टे के बारे में जानकारी मिली, तब से हमेशा यहां आने का मन करता। उनकी पत्नी ने कहा कि यहां अच्छा और शांति पूर्ण वातावरण है। हमारा बच्चा यहां बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा है। मोबाइल और टीवी से दूर है। लोगों को डील कर रहा हैं। उनके बेटे यथार्थ सिंह ठाकुर ने बताया कि मेरे यहां बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है।

पर्यटन गांव का दर्जा मिलने से सूरत बदली, विस्थापन रुका – सावरवानी की नेहा यदुवंशी बताती हैं कि उनके पिता नहीं हैं, मां ने मजदूरी कर पढ़ाया। लेकिन होम स्टे की ट्रेनिंग के बाद हम आत्मनिर्भर होकर अपना खर्च खुद उठा रहे हैं। ग्रामीण महिला ने बताया कि पहले गांव में पीने का पानी और पर्याप्त साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन होम स्टे बनने के बाद इनमें सुधार आया है। लोगों को रोजगार मिला है। पर्यटकों को बैलगाड़ी से गांव घुमाने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि पहले काम की तलाश में दूसरे जिलों में जाना पड़ता था लेकिन होम स्टे शुरू होने के बाद अच्छी आमदनी हो रही है। गांव का एक चक्कर घुमाने पर पर्यटक 300 रुपए टिप देते हैं। शाम के समय गांव के लोकल ट्राइबल ग्रुप शैला लोक नृत्य से पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं।

बिजली के मामलों को लेकर अंतरविभागीय समिति होगी गठित

कलेक्टर-एसपी के पास होगी बकायादारों के परिजनों की बैंक डिटेल, वसूली कराएंगे

भोपाल (नप्र)। अब जिलों में कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त बिजली के बकाया की वसूली करवाएंगे। बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के परिजनों के बैंक खातों की डिटेल भी इन अधिकारियों के पास होगी। कौन उपभोक्ता गलत सब्सिडी ले रहा है, यह भी मालूम करेंगे। दरअसल राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय विद्युत अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होंगे। पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के एसई और ओएंडएम के महाप्रबंधक सदस्य एवं संयोजक होंगे।

समिति के पास होंगी ये जिम्मेदारियां

- बकाया राशि वाले क्षेत्रों एवं उपभोक्ताओं को चिह्नांकित करना।
- उपभोक्ताओं का केवाईसी करवाना, जिससे डाटा एनालिसिस के आधार पर पात्र उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके।
- ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करना, जो जान-बूझकर लंबे अरसे से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं।
- समिति उपभोक्ताओं व उनके परिजनों के बैंक खातों की जानकारी लेकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग (ड्यूज़ रिकवरी) एक्ट 1961 के अंतर्गत बैंक खाते के माध्यम से राशि वसूलेंगे।
- वसूली के दौरान बिजली कर्मियों के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार और मारपीट की स्थिति में दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- अवैध कालोनी सहित अन्य रहवासी क्षेत्रों में बिजली चोरी की रोकथाम के प्रति जन जागरूकता अभियान शुरू कराएंगे
- अवैध कॉलोनी के प्रकरणों में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए योजना तैयार करेंगे।
- भोपाल में बिजली कंपनी ने 1400 से ज्यादा ऐसे घर चिह्नित कर लिए हैं, जहां एक से ज्यादा मीटर लगे हैं। कंपनी द्वारा अब इनके बिलों का एनालिसिस किया जा रहा है।

अब ट्राइबल का खुद का टेक्निकल विंग बनायेगा जनजातीय विकास की अधोसंरचनाएँ

● टेक्निकल विंग के लिये 177 पद मंजूर

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में जनजातियों के विकास से जुड़ी सभी प्रकार की अधोसंरचनाएँ अब जनजातीय कार्य विभाग का खुद का टेक्निकल विंग बनायेगा। विभाग में नये टेक्निकल विंग की स्थापना की गई है। राज्य शासन द्वारा ट्राईबल टेक्निकल विंग सेट-अप को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिये 177 नये पद भी शासन ने स्वीकृत किये हैं। इसमें अधीक्षण यंत्री (एस.ई) का एक पद, कार्यपालन यंत्री (ई.ई) के 6, सहायक यंत्री (सिविल) के 25, सहायक यंत्री (विद्युत) के 3, उपयंत्री (सिविल) के 123, उपयंत्री (विद्युत) के 9, प्रगति सहायक के 7 तथा निर्माण सहायक, सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक के एक-एक पद को मंजूरी दी गई है। पदों की मंजूरी मिलने के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विभागीय स्तर या अन्य शासकीय भर्ती एजेन्सीज के माध्यम से टेक्निकल विंग स्टॉफ की भी जल्द से जल्द भर्ती की जायेगी। ट्राईबल टेक्निकल विंग के हेड अधीक्षण यंत्री (एसई) होंगे, जो जनजातीय कार्य मुख्यालय से विभागीय निर्माण कार्यों का सुपर विजन करेंगे। इनके अधीन 6 ईई होंगे। एक ईई मुख्यालय के कार्यों के अलावा भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों का काम देखेंगे। एक ईई इंदौर मुख्यालय से इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों का काम संभालेंगे। सागर और जबलपुर संभाग के जिलों के कार्यों के लिये भी एक-एक ईई को दायित्व सौंपा गया है। ग्वालियर के ईई ग्वालियर के साथ-साथ चंबल संभाग तथा शहडोल में पदस्थ ईई शहडोल सहित रीवा संभाग के सभी जिलो में विभागीय निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराने तथा मॉनीटरिंग के लिये उत्तरदायी होंगे।

बीच सड़क पर रोका, 3 गोलियां मारीं

हत्या की सजा काट रहे युवक का मर्डर ; कनाडा से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक

डबरा (नप्र)। ग्वालियर जिले के डबरा में दो बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने एक के बाद एक तीन गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस युवक की हत्या की गई, वह भी हत्या के आरोप में आजीवन कारावास काट रहा था। 28 अक्टूबर को पैरोल पर छूटकर जेल से घर आया था।

पुलिस ने बताया कि गोपाल बाग सिटी का रहने वाला जसवंत सिंह गिल उर्फ सोनी सरदार (45) खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था। वह कुछ लोगों से बात करने के लिए रुका। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां आए। एक युवक मोटरसाइकिल से उतरा और जसवंत को आवाज दी। जसवंत के पलटते ही उसे गोलियां मार दीं। फिर बाइक पर बैठकर दोनों भाग निकले।

पत्नी के ममेरे भाई की हत्या की थी – जसवंत सिंह गिल मूल रूप से कैथी गांव का रहने वाला था। 2016 में उसने ग्वालियर जिले के महाराजपुर में सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में उसके माता-पिता घायल हो गए थे। सुखविंदर जसवंत की पत्नी के मामा का बेटा था। सुखविंदर का बड़ा भाई सतपाल सिंह कनाडा में रहता है। वह कुछ दिन पहले अपने परिवार से मिलने ग्वालियर आया था। इसी मामले में 2018 में जसवंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह बीच-बीच में पैरोल पर घर आता-जाता रहता था।

कॉलोनी का चौकीदार छुट्टी पर था – गोपाल बाग सिटी के रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी के गेट पर चौकीदार तैनात रहता है लेकिन वह बीते 2 दिन से छुट्टी पर है। जिसके चलते कॉलोनी का गेट खुला था। यही कारण रहा कि हमलावर आए और बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

चेहरा नहीं छिपाया, पिस्तौल अटकने के बाद भी ट्रिगर दबाया – वारदात के दौरान हमलावर पूरी तरह बेखौफ दिखे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि हत्यारों ने अपना चेहरा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वे कॉलोनी में घुसे और एक जगह खड़े हो गए। जब जसवंत टहलने निकला तो तीन लोगों की मौजूदगी में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि तीन गोलियां मारने के बाद हत्यारे की पिस्तौल अटक गई। वह फिर भी ट्रिगर दबाता रहा।

भोपाल उत्सव मेला... 10 एकड़ जमीन पर फैला रहेगा, तैयारियां जोरों पर चल रहीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल उत्सव मेला इस बार 10 एकड़ जमीन पर फैला रहेगा। टीटी नगर दशहरा मैदान पर इन दिनों मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले का यह 32वां साल है। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक लगने वाले मेले में करीब 500 प्रतिष्ठानों के स्टॉल्स बिक्री और सामान के डिस्प्ले के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनमें फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल, घरेलू उपकरण, हैंडलूम के अलावा फूड जोन और सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला सामान शामिल है। इस बार मेले में फिश टनल, मारुति सर्कस कुआं के अलावा सुनामी, रेंजर, डबल डिस्क, मेरी ग्राउंड सहित अन्य कई झूले रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन, फिल्म स्टार नाइट, लाफ्टर शो, गजल, सिंगिंग एंड डांस कॉम्पटीशन सहित कई तरह के आयोजन मेला स्थल पर होंगे।

वीआईटी–भोपाल की राज्यपाल से हुई शिकायत, आयोग ने बनाई 5 सदस्यीय जांच कमेटी

भोपाल (नप्र)। भोपाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने वीआईटी-भोपाल में छात्रों के दुर्व्यवहार होने और अनियमितताओं होने की शिकायत राज्यपाल से की है। इसको लेकर मध्यप्रदेश निजी विवि विनियामक आयोग ने शासकीय हमीदिया कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर डॉ. अनिल शिवानी की अध्यक्षता में चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। आयोग के चेयरमैन प्रो. भरत शरण सिंह का कहना है कि वीआईटी भोपाल को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ईमेल से भी शिकायत प्राप्त हुई। छात्रों में असंतोष है। प्रदर्शन भी हुए। हैं। राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री तक शिकायतें पहुंची हैं। कमेटी गठित कर जांच करने आदेश जारी किए हैं। आरोप हैं कि पिछले दिनों विवि के छात्रावास में एक छात्रा द्वारा अन्य छात्राओं के नहाते हुए वीडियो वायरल किया गया। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत करने का प्रयास किया तो 74 छात्र छात्राओं को निलंबित कर दिया, 12 छात्र-छात्राओं को स्थाई रूप से निलंबित किया। एबीवीपी ने पेयजल सहित छात्र संख्या, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल केंटीन की जांच और वर्तमान में संचालित कोर्स और उनकी फैकल्टी की जांच करने सहित इस तरह 15 बिंदुओं की शिकायत की गई है। इधर, हाल ही में वीआईटी ने कक्षा में उपस्थिति कम होने के कारण इंट्रिम सेमेस्टर 2024-25 मिड टर्म एग्जामिनेशन-2024 से 400 से ज्यादा छात्र-छात्राओं को डी-बार किया है। ट्रऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। जिसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। विवि की छवि खराब करने की प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने विवि की छवि खराब करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 5 नवंबर को जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम से डी-बार किया गया है, उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। ये विवि की रेगुलर प्रैक्टिस है। जो छात्र नियमानुसार कक्षाओं में नहीं पहुंचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा सभी विवि में होता है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन ने 'विकसित मध्यप्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेंट, वर्ष 2028 तक के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, उच्च शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पर्यटन, वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग समिति में सदस्य सचिव होंगे। उच्चाधिकार समिति द्वारा 'विकसित मध्यप्रदेश 2047' विजन डॉक्यूमेंट, वर्ष 2028 तक के लक्ष्य तथा एक्शन पॉइंट्स के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करना, कार्यसमूहों एवं उनसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, विभागीय चर्चा के आउटपुट की समीक्षा, शासन द्वारा चयनित बाह्य एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। समिति अंतिम प्रारूप का अनुमोदन कर आगामी कार्यवाही के लिए नोडल विभाग को प्रेषित करेगी।

मदरसा बोर्ड की परीक्षा के संबंध में सूचना

भोपाल(नप्र)। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त और राज्य शिक्षा केन्द्र से डाइस कोड प्राप्त मदरसों की वर्ष 2024-25 की वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य शिक्षा केन्द्र के दिशा-निर्देश एवं समय-सारणी अनुसार होगी। इसकी सूचना प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को दी जा चुकी है। निर्देशों में कहा गया है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के बनाने का कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र के ब्लूप्रिंट के अनुसार होगा करेगा। प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्रों की एक-एक प्रति बीआरसी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाये। इस संबंध में अन्य जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

लेडी अफसर ने हाईकोर्ट वकील को धक्का देकर निकाला

भोपाल में हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ की कुर्की कराने आए थे; सामान बाहर रखा

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल स्थित मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हंगामा मच गया, जब कोर्ट के कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर दफ्तर का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां पदस्थ एक लेडी अफसर ने कार्रवाई का विरोध किया। उन पर कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है। दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट ने एक मामले में मध्यप्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया था। इसी का पालन कराने के लिए कर्मचारी यहां पहुंचे थे।

महिला अधिकारी ने वकील को दफ्तर से बाहर निकाला – कोलकाता हाईकोर्ट के वकील शुक्रवार को भोपाल कोर्ट के अधिकारियों के साथ भोपाल के जेपी हॉस्पिटल कैंपस में स्थित स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर पहुंचे। कोर्ट के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संचालनालय में रखा सामान निकालना शुरू कर दिया। इस बीच स्वास्थ्य संचालक मल्लिका निगम नागर की ओर से कहा गया कि यहां स्वास्थ्य निदेशक का कोई पद नहीं है। ऐसे में आप इस दफ्तर में कुर्की नहीं कर सकते हैं। कंपनी के वकील के साथ स्वास्थ्य संचालनालय की एक महिला अधिकारी ने उन्हें ऑफिस से बाहर कर दिया। वकील ने भोपाल कोर्ट में इस बर्ताव की शिकायत करने और अतिरिक्त पुलिस बल मांगने की बात कही है। स्वास्थ्य संचालनालय में एडिशनल डायरेक्टर ने कुर्की करने पहुंची टीम को बाहर कर दिया।

कोलकाता हाईकोर्ट ने कुर्की के आदेश क्यों दिए – दरअसल, कोलकाता की एक कंपनी से मध्यप्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने साल 2013 में कीटनाशक दवाएं खरीदी थी, जिसका पेमेंट नहीं किया गया। इसके खिलाफ कंपनी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कंपनी को ब्याज समेत राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए कंपनी ने भोपाल जिला कोर्ट में एक्जीक्युशन याचिका लगाई। इस पर भोपाल कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया।

वकील बोले- स्वास्थ्य विभाग सुप्रीम कोर्ट तक में केस हारा – कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने बताया- हेल्थ डायरेक्टर एमपी को नीटापोल इंडस्ट्री ने 2013 में इन्सेक्टिसाइट सप्लाई किया था। मेसर्स नेटापोल इंडस्ट्री इन्सेक्टिसाइट की मैन्युफेक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। विभाग ने 50 लाख 70 हजार रुपए कीटनाशक दवाएं ले ली और उपयोग करने के बाद अब तक भुगतान नहीं किया। इसको लेकर हम लोगों ने पश्चिम बंगाल फेसिलेशन काउंसिल में रेफरेंस एप्लीकेशन लगाई थी। काउंसिल ने आरबीआई के अनुसार ब्याज सहित राशि अदा करने का आदेश दिया था। उसमें ये लोग (स्वास्थ्य विभाग) हार चुके हैं। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में उन लोगों ने केस दायर किया। वहां भी ये लोग हार चुके हैं। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहां भी डायरेक्टर हेल्थ हार गए। एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने बताया कि मप्र स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने मिसबिहेव किया और ऑफिस से निकाल दिया।

स्वास्थ्य संचालक ने कहा- यहां स्वास्थ्य निदेशक का पद नहीं – कंपनी के वकील ने कहा- इसके बाद हम लोगों ने भोपाल जिला न्यायालय की कमर्शियल बेंच में एक्जीक्युशन की याचिका लगाई। भोपाल जिला न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ की कुर्की का आदेश दिया था। वकील ने कहा-हम लोग यहां कुर्की करने आए थे। यहां की जो अधिकारी हैं मल्लिका निगम नागर यहां की डायरेक्टर (आईएएस) हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि यहां पर निदेशक, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ का कोई पोस्ट ही नहीं हैं आप यहां की कुर्की नहीं कर सकेंगे। हम लोगों ने थोड़ा सा सामान निकाला, वो लोग हमें लिखकर दे रहे हैं कि ये निदेशक हेल्थ का ऑफिस नहीं हैं। कंपनी से 50 लाख 70 हजार का सामान खरीदा था ब्याज मिलाकर कोर्ट ने 19 करोड़ 34 लाख 57 हजार 58 रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं।

मिसबिहेव किया गया, कोर्ट को अवगत कराएंगे – कंपनी के वकील पूर्णाशीष भुइया ने कहा- हम कोर्ट के ऑर्डर पर कोर्ट के स्टाफ के साथ कुर्की करने आए थे, यहां की अधिकारी ने मिसबिहेव किया और ऑफिस से निकाल दिया। हम कोर्ट को इसकी जानकारी देकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कुर्की कराने का अनुरोध करेंगे।

भोपाल जिपं की मीटिंग में उठा खाद-पानी का मुद्दा

सदस्य मेहर बोले– किसानों को खाद नहीं मिल रहा ; मेरे पास वीडियो

भोपाल (नप्र)। भोपाल जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग शुक्रवार को हुई। इसमें उपाध्यक्ष मोहन जाट, सदस्य विनय मेहर, चंद्रेश राजपूत और विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने खाद, पानी और आंगनवाड़ी केंद्र के जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया। सदस्य मेहर ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। मेरे पास परेशान किसानों के वीडियो है। जनप्रतिनिधियों के उठाए मुद्दों पर सीईओ ऋतुराज सिंह ने भी अफसरों को निर्देश दिए। कहा कि समस्याएं तुरंत दूर की जाए। ढाई घंटे चली बैठक बिना हंगामे के खत्म हो गई। अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे से बैठक शुरू हुई, जो 3.30 बजे तक चलती। इसमें कुल 15 विभागों की समीक्षा की गई। सीईओ सिंह ने बैठक का एजेंडा रखा। इसके बाद विभागों की समीक्षा शुरू हुई। उपाध्यक्ष जाट ने उप संचालक कृषि से कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद मिले और उसकी कालाबाजारी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। विधायक प्रतिनिधि गुर्जर ने कहा कि कई गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। पानी की समस्या भी है। इसे दूर किया जाना चाहिए। सदस्य मेहर ने कहा कि कई गांवों में पानी की समस्या है, लेकिन पीएचई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। 70 प्रतिशत गांवों में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इस पर सीईओ सिंह ने पीएचई अधिकारी से कहा कि किसी भी गांव में पानी की समस्या न आए। इसका ध्यान रखा जाए।

सड़क की स्थिति ठीक नहीं-गुर्जर – विधायक प्रतिनिधि गुर्जर ने सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले की कई सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। बारिश के बाद इन्हें सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें तुरंत ठीक किया जाए।

सीईओ बोले- तुरंत सुधार भवन – अध्यक्ष गुर्जर, उपाध्यक्ष जाट समेत सदस्यों के मुद्दों पर सीईओ सिंह ने अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए। उनके मोबाइल कॉल जरूर रिसीव करें।

सदस्यों की एंट्री नहीं –इससे पहले दोपहर 12 बजे से सामान्य प्रशासन समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रतिनिधियों की एंट्री नहीं हुई। सीईओ सिंह ने इसे लेकर समिति सभापति को लेटर भी लिखा था।

इन मुद्दों पर चर्चा – बैठक में कृषि, पशु चिकित्सा, मत्योद्योग, सहकारी समिति, बिजली कंपनी, वन, पीएचई, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई।

इसलिए जरूरी है मीटिंग – जानकारी के अनुसार, बैठक ही एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जहां सभी विभागों के अफसरों से जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रूबरू होते हैं। पिछली बैठकों में उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अधिकारियों पर भड़ास भी निकाली थी। इसके बाद कामों में थोड़ी तेजी आई, लेकिन बैठक न होने से गांव के विकास से जुड़े काम अटक गए। सदस्यों का कहना है कि बैठक न होने से वे गांव से जुड़े पानी, सड़क, नाला-नाली निर्माण, बिजली कनेक्शन समेत जनता से जुड़े अन्य विषय नहीं उठा पा रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली बैठक में ये मुद्दे उठाए।

दो महीने में होनी चाहिए मीटिंग – पिछली 2 मीटिंग को 9 महीने का समय हो चुका है। नियमानुसार,मीटिंग हर दो महीने में होनी चाहिए।

किसानों के चक्काजाम में फंसी एंबुलेंस

● खाद–बीज नहीं मिलने पर जबलपुर–दमोह मार्ग पर लगाया जाम, मौके पर पहुंचे अधिकारी

जबलपुर (नप्र)। शुक्रवार की दोपहर खाद-बीज नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने जबलपुर-दमोह मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। जिसके चलते करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी। किसानों ने जबलपुर-दमोह सड़क मार्ग पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई। इस बीच पाटन से जबलपुर जा रही एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। जैसे-तैसे मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे बाहर निकाला।

किसानों का कहना है कि, एक सप्ताह से डीएपी और बीज नहीं मिल रहे हैं। बार-बार प्रशासन को अपनी समस्या बताई, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसान राज सिंह ने बताया कि, गुरु पिपरिया में स्थित डबल लॉक केन्द्र से पाटन तहसील के 100 से ज्यादा किसानों को खाद और बीज बांटा जाता है। बार-बार मांग के बाद भी जब किसानों के लिए खाद-बीज की व्यवस्था नहीं हो पाई तो नाराज किसान सड़क पर उतर आए। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा खाद-बीज की किल्लत से परेशान होकर किसानों ने जाम लगा दिया था। समझाइश के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया।

15 नवंबर से तेज ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

एमपी में सबसे सर्द पचमढ़ी ; उत्तरी हवाएं लाएंगी तापमान में गिरावट

भोपाल (नप्र)। नवंबर की शुरुआत से ही मध्यप्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान है। यहां दिन और रात दोनों ही सर्द हैं। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, कई शहरों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में मंडला, उमरिया, राजगढ़, गुना समेत कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने बताया-नवंबर के दूसरे सप्ताह में हवा का रुख बदल जाएगा। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे पारे में गिरावट आएगी। खासकर प्रदेश के उत्तरी हिस्से ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में सर्दी बढ़ जाएगी। नवंबर के आखिरी में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है।

ये शहर सबसे ठंडे

- मौसम विभाग के अनुसार, पिछली 7 रातों में से 6 बार पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है। एक बार अमरकंटक सबसे सर्द रहा था। बुधवार–गुरुवार की रात में भी पचमढ़ी में पारा 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
- शाजापुर, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल, राजगढ़, भोपाल, बैतूल, टीकमगढ़, मलाजखंड, रायसेन, उमरिया, उज्जैन, नौगांव, खरगोन और रतलाम ऐसे शहर हैं, जहां तापमान 18 डिग्री से कम रहा। वहीं, गुरुवार को दिन में पचमढ़ी समेत कई शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा।

भोपाल के बैरागढ़ में 3 कपड़ा दुकानों में आग

75 लाख के कपड़े और गृहस्थी का सामान जला, आधा दर्जन दमकलों ने डेढ़ घंटे में काबू किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर) में शुक्रवार तड़के 5 बजे 3 कपड़ा दुकान और एक फ्लैट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट तक आग पहुंच गई। इससे रखा गृहस्थी का सामान जल गया।

आग पर करीब डेढ़ घंटे में काबू पाया गया। बैरागढ़, फतेहगढ़, गांधीनगर समेत अन्य फायर स्टेशनों से आधा दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है।

दो मंजिला बिल्डिंग, नीचे दुकानें और ऊपर मकान – दो मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की रिटेल दुकानें हैं। इसके ऊपर फ्लैट है और फिर सेकंड फ्लोर खाली है। मेन रोड पर सुरेश इलेक्ट्रिक के पास स्थित इस बिल्डिंग में सबसे पहले एक कपड़ा दुकान में आग लगी। जिसने दो दुकानों को और चपेट में ले लिया। धीरे-धीरे आग फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई और भीषण हो गई। हालांकि, फ्लैट खाली था। इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का गृहस्थी का सामान जल गया।

बैरागढ़ में कपड़ों का थोक मार्केट – बैरागढ़ में कपड़ों का थोक मार्केट है। जिन दुकानों में आग लगी, ठीक उसके पीछे थोक दुकानें थी। यदि आग ज्यादा भीषण होती तो अन्य दुकानें भी चपेट में आ जाती।

शटर बंद होने से आग बुझाने में दिक्कत – आग लगने की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे फायर अमले के सामने बंद शटर बड़ी परेशानी बन गई। शटर को जैसे-तैसे नीचे से खोला गया। इसके बाद आग बुझाई गई। आग जल्दी काबू में आ गई, लेकिन अंदर रखा कपड़ा पूरी तरह से जल चुका था।

प्रॉपर्टी के रेट कब से बढ़ेंगे, सरकार करेगी फैसला

मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे अफसर, एक और बैठक करेगी केंद्रीय मूल्यांकन समिति

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में एक साल के भीतर दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से चर्चा के बाद होगा। इसके बाद ही 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति से हरी झंडी पाने वाली लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके आधार पर रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क वसूला जाएगा। आईजी पंजीयन और मुद्रांक विभाग के अधीन काम करने वाली कमेटी ने यह भी तय किया है कि एक हफ्ते में एक और मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू करने के मामले में होल्ड किए गए भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी।

इसके लिए भोपाल कलेक्टर को सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद एक हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय मूल्यांकन समिति इसी बैठक में सीहोर और श्योपुर जिले की कलेक्टर गाइडलाइन को भी दोबारा अनुमोदित करेगी, क्योंकि अभी वहां 13 नवंबर को वोटिंग होना है। इसलिए इन जिलों की जिला मूल्यांकन समिति की कलेक्टर गाइडलाइन रिपोर्ट को लागू करने से रोका गया है।

1 लाख 12 हजार लोकेशन में से 3500 पर बढ़ेंगे दाम – प्रदेश भर के 1 लाख 12 हजार लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को मिले थे। इसमें से 3 प्रतिशत यानी 3500 लोकेशन पर 0.94 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया जा चुका है। अधिकारी इस मामले में किसी तरह की विवाद की स्थिति में नहीं उलझना चाहते हैं, इसलिए तय किया गया है कि इस वृद्धि को सरकार को संज्ञान में लाकर ही बढ़े दाम प्रभावी करने की तारीख का ऐलान किया जाए।

अफसरों के अनुसार जहां कलेक्टर गाइडलाइन में बताई गई प्रॉपर्टी की कीमत और आज के बाजार मूल्य में बहुत अधिक अंतर पता चला है, उसी लोकेशन को चिन्हित कर उसी क्षेत्र में ही कीमत बढ़ाई है।

कीमतें बढ़ाने वाली केंद्रीय मूल्यांकन समिति में ये अफसर

- आईजी पंजीयन और मुद्रांक
- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग
- संचालक नगर व ग्राम निवेश
- आयुक्त भू अभिलेख
- संचालक कृषि और किसान कल्याण विभाग
- मुख्य वन संरक्षक वन विभाग
- विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग मैनिट
- विभागाध्यक्ष आर्किटेक्चर विभाग मैनिट ओएसडी वाणिज्यिक कर विभाग
- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के परिक्षेत्रीय डीआईजी पंजीयन

संपादकीय

शरद पवार का इमोशनल कार्ड!

लगता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख घटक अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने फिर इमोशनल (भावनात्मक) कार्ड यह कहकर खेला है कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। अर्थात उनका मन अब राजनीति से संन्यास लेने का हो रहा है। इस बयान के कई अर्थ निकाले जाने लगे। हालांकि इस वक्तव्य के दूसरे ही दिन उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने इस अटकल का खंडन कर दिया कि शरद पवार सियासत से रिटायर होने का मन बना रहे हैं। अपने गृह क्षेत्र बारामती के शिरसुफल में अपने पोते और राकांपा (शरद) के उम्मीदवार युगेन्द्र पवार के पक्ष में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चुनाव को लेकर मुझे अब रुकना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अब तक 14 बार चुनाव लड़ा हूं, सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहता हूं। पवार ने यह भी कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूं। मैं राज्यसभा में हूं। मेरे पास अभी भी डेढ़ साल का वक्त बाकी है। डेढ़ साल बाद मुझे सोचना होगा कि राज्यसभा जाऊं या नहीं। लोकसभा तो मैं नहीं लड़ूंगा। कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितने चुनाव लड़े जाएं? आपने (जनता) ने एक बार भी घर नहीं बैठाया मुझे। हर बार मुझे निर्वाचित कर रहे हैं तो कहीं तो थमना ही चाहिए। मैंने इस सूत्र पर काम करना शुरू कर दिया है कि नई पीढ़ी को अब आगे आना चाहिए। यही नहीं उन्होंने राज्य के उपमुख्यमंत्री और अपने भतीजे अजित पवार के काम को सराहा, लेकिन यह भी कहा कि अगले तीन दशकों तक इस क्षेत्र के विकास के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है। गौरतलब है कि पवार ने राकांपा प्रत्याशी अजित पवार के खिलाफ अपने पोते युगेन्द्र को मैदान में उतारा है। यानी पवार खानदान में दूसरी बार आपसी लड़ाई है। पहली लड़ाई लोकसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें अजित पवार ने राकांपा (शरद) प्रत्याशी और अपने चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था, जिसमे सुनेत्रा भारी अंतर से हार गई थीं। बारामती विस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट के इशारे के साथ साथ अजित पवार को भी संन्यास लेने का संदेश दे दिया। उनका कहना था कि अब हमे तीसरी पीढ़ी को तैयार करना है, जो आगे 30 साल तक नेतृत्व कर सके। लिहाजा सभी को अवसर मिलना चाहिए। इस बार बारामती की जनता किस के पक्ष में निर्णय देगी, यह तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन अगर अजित पवार यह चुनाव हार गए तो उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नचिन्ह जरूर लग जाएगा,राज्य का मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है। हालांकि वो अभी भी आत्मविश्वास से भरे हैं और अपने चाचा शरद पवार को कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में मैंने जो गलती की, वही आप विधानसभा में दोहरा रहे हैं। वैसे शरद पवार इस तरह का इमोशनल कार्ड पहले भी खेलते रहे हैं। जुलाई 2023 में भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट के संकेत दिए थे। लेकिन बाद में उसका भी खंडन हो गया। इसी से नाराज होकर अजित पवार ने बगावत का रास्ता चुना। अगर समय रहते पवार पार्टी की बागडोर अजित के हाथों में सौंप देते तो पार्टी टूटने की नौबत ही नहीं आती। दरअसल शरद पवार उन नेताओं में से हैं, जो चौबीसों घंटे राजनीति में ही रमते हैं। ऐसे में उम्र के 84 वे वर्ष में भी वो पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

नजरिया

ललित गर्ग
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समृद्धि के उजालों के बावजूद धनाढ्यों का पलायन क्यों?

इस बार की दीपावली न केवल खुशी, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का अवसर बनी है, बाजार से समाज तक और उद्यमी से सरकार तक, सभी के लिये दीपावली समृद्धि का एक नया उजाला लेकर आयी। इस बार बाजार में कुल 4.25 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी का अनुमान है। देश के ज्यादातर उद्यमी खरीद-बिक्री के अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। सरकार को फायदा है कि लगभग हर खरीद-बिक्री से उसे लाभ होना है। देश में खरीद-बिक्री का यह विस्तार निश्चित ही जहां भारत में नये आर्थिक कीर्तिमान का द्योतक हैं, वहीं गरीब को सक्षम बनाने का प्रेरक भी है। समाज का एक बड़ा वंचित हिस्सा है, जिसमें खरीदारी की ज्यादा ताकत नहीं है। वास्तव में, गरीबों को सक्षम बनाना, केवल सरकार ही नहीं, बल्कि बाजार की भी जिम्मेदारी है। आधुनिक दौर में सरकार लोगों को सीधे नकद देकर सक्षम बनाती है, तो बाजार को भी लोगों को सक्षम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। उद्यमी जो पूंजी अर्जित कर रहे हैं, उसे कहीं जमा करने या सिर्फ अपना उपभोग बढ़ाने के बजाय निवेश में लगाएं। निवेश से रोजगार और काम पैदा हो, यह ज्यादा जरूरी है।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने के साथ समृद्धि और संपन्नता के नये शिखरों पर आरोहण कर रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश में सोने का भंडार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, दूसरी तरफ डीमैट खातों और स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन सकारात्मक दिशाओं एवं आर्थिक उजालों के बीच कुछ देश की सोचने वाली स्थितियां भी हमें आत्ममंथन को प्रेरित कर रही है। ऐसी ही एक सोचनीय एवं चिन्ताजनक स्थिति है कि देश की बढ़ती शोभा एवं सम्पन्नता के बावजूद अमीर व प्रतिभावान लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वर्ष 2023 में करीब इक्कावन सौ के लगभग करोड़पतियों ने देश छोड़ा और वर्ष 2024 में तैयालिस सौ करोड़पतियों के भारत से पलायन करने का अनुमान है। यह हमारी संपन्नता का ही क्षरण एवं हमारी आर्थिक विकासमूलक यात्रा पर एक बदनुमा दाग है। इन स्थितियों पर नियंत्रण जरूरी है और इसके लिये हमें अपनी कमियों के प्रति ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर निर्मित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। बुनियादी ढांचागत विकास को प्राथमिकता देने के लिये हमें मौजूदा सरकार की सराहना करनी ही चाहिए। आर्थिक वृद्धि को आवश्यक आधार प्रदान करने के साथ ही बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी आवश्यक होती है। मोदी सरकार की नियोजित एवं दूरगामी सोच का ही परिणाम है रिजर्व बैंक के पास सोने के भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है, पूर्व सरकारें देश का सोना गिरवी रखती रही है, लेकिन मोदी सरकार देश का सोना विदेशों से स्वदेश लाने के अनूठे उपक्रम किये हैं, यही कारण है कि रिजर्व बैंक के पास सितंबर में सोने का भंडार 854.73 टन था। इसमें से 510.46 टन देश में है, बाकी 324.01 टन सोना विदेशी बैंकों में है। आरबीआई सोना खरीदने वाले पांच शीर्ष केंद्रीय बैंकों में से एक है। भारतीयों के पास घरों में 25 हजार टन से ज्यादा सोना है। यह स्वर्ण भंडार में पहले पायदान पर खड़े अमेरिका के 8,965 टन से तीन गुना है।

भारत में आर्थिक गतिविधियां नये शिखरों पर सवार है, क्योंकि भारत में डीमैट खाते 17 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश के कुल डीमैट खाते अब अन्य देशों की तुलना में नौवें स्थान पर हैं, जिसका मतलब है डीमैट खाते रूस, जापान, इथियोपिया, मैक्सिको जैसे देशों की आबादी से अधिक और बांग्लादेश की आबादी के करीब है। वर्ष 2024 में 3.18 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए। पिछले वर्ष 3.10 करोड़ डीमैट खाते खोले गए थे। भारत दुनिया तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1,40,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और हर 20 दिन में एक यूनिकॉर्न उभरता है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है, जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर हो जाता है। इस बार जनवरी से सितम्बर के बीच छह स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। भारतीय तकनीकी स्टार्टअप ने 2024 की पहली छमाही में 4.1 अरब डॉलर की फडिंग जुटाई जो बीते वर्ष की इसी छमाही से 4 फीसदी ज्यादा है। फडिंग जुटाने में भारत का चौथा स्थान है। इन उजले आंकड़ों में जहां मोदी के विजन 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर भारत ने अनेक क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित किये है। लेकिन श्रम शक्ति की ओर ज्यादा तवज्जों देने की जरूरत है। क्योंकि जीडीपी देश के आम नागरिकों की समृद्धि का पैमाना नहीं है। जिस पैमाने से देश के आम लोगों की समृद्धि मापी जाती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसमें दिहाड़ीदार मजदूर, कामकाजी लोग, महिलाओं की स्थिति से लेकर औद्योगिक घराने की कमाई तक सब शामिल रहते हैं। बहुत सारे लोग औसत से अधिक कमाते हैं और बहुत सारे लोग कम।

इस बार की दीपावली न केवल खुशी, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का अवसर बनी है, बाजार से समाज तक और उद्यमी से सरकार तक, सभी के लिये दीपावली समृद्धि का एक नया उजाला लेकर आयी। इस बार बाजार में कुल 4.25 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी का अनुमान है। देश के ज्यादातर उद्यमी खरीद-बिक्री के अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। सरकार को फायदा है कि लगभग हर खरीद-बिक्री से उसे लाभ होना है। देश में खरीद-बिक्री का यह विस्तार निश्चित ही जहां भारत में नये आर्थिक कीर्तिमान का द्योतक हैं, वहीं गरीब को सक्षम बनाने का प्रेरक भी है। समाज का एक बड़ा वंचित हिस्सा है, जिसमें खरीदारी की ज्यादा ताकत नहीं है। वास्तव में, गरीबों को सक्षम बनाना, केवल सरकार ही नहीं, बल्कि बाजार की भी जिम्मेदारी है। आधुनिक दौर में सरकार लोगों को सीधे नकद देकर सक्षम बनाती है, तो बाजार को भी लोगों को सक्षम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। उद्यमी जो पूंजी अर्जित कर रहे हैं, उसे कहीं जमा करने या सिर्फ अपना उपभोग बढ़ाने के बजाय निवेश में लगाएं। निवेश से रोजगार और काम पैदा हो, यह ज्यादा जरूरी है।

नयी आर्थिक उपलब्धियों एवं फिजाओं के बीच धनाढ्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। ऐसे क्या कारण है कि लोगों को देश की बजाय विदेश की धरती रहने, जीने, व्यापार करने, शिक्षा एवं रोजगार के लिये अधिक सुविधाजनक लगती है, नये बनते भारत के लिये यह चिन्तन-मंथन का कारण बनना चाहिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च निवल मूल्य वाली व्यक्तिगत आबादी के 2031 तक 80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इस अवधि के दौरान भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते धन बाजारों में से एक के रूप में स्थापित करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देश के भीतर संपन्न वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी। इसमें समृद्ध व्यक्तियों के भारत लौटने की प्रवृत्ति को भी देखा जा रहा है, और जैसे-जैसे जीवन स्तर में सुधार जारी है, यह अधिक संख्या में धनवान व्यक्तियों के भारत वापस आने का अनुमान लगाता है। लेकिन प्रश्न है कि भारत के करोड़पति आखिर नये बनते भारत एवं उसकी चिकित्सा, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक उज्ज्वलता के बावजूद क्यों विदेश जा रहे हैं? हाई नेटवर्थ वाले (अति समृद्ध) हमारे देशवासियों के देश छोड़ कर कहीं और बसने की तैयारी की ताजा रिपोर्टें बहुत कुछ कहती है। दुनियाभर में धन और निवेश प्रवासन के रुझान को ट्रैक करने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट में अति समृद्ध भारतीयों का अपना सब-कुछ समेट कर हमेशा के लिए भारत से जुदा हो जाने का अनुमान अनेक प्रश्न खड़े करता है, सरकार को इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है।

क्या कारण है कि शस्य श्यामला भारत भूमि पर अपनी समृद्धि से विकास के नये क्षितिज उद्घाटित करने या अपनी प्रतिभा से देश को लाभान्वित करने की बजाय विदेश की धरती को लाभ पहुंचाते हैं। कारणों की लम्बी फहरिस्त में मूल है देश में अशांति, आतंक, जटिल कर-कानून व्यवस्था और हिंसा का ताण्डव होना? कारण है -शासन, सत्ता, संग्रह और पद के मद में चूर यह तीसरा राजनीतिक आदमी, जिसने जनतंत्र द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग किया और जनतंत्र की रीढ़ को तोड़ दिया है। कृषि प्रधान देश को कुर्सी-प्रधान देश में बदल दिया है। सरकारें हैं-प्रशासन नहीं। कानून है..न्याय नहीं। साधन हैं-अवसर नहीं। भ्रष्टाचार की भीड़ में राष्ट्रीय चरित्र खो गया है। पलायनवादी सोच के कगार पर खड़े राष्ट्र को बचाने के लिए राजनीतिज्ञों को अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति को त्यागना होगा। तभी समृद्ध हो या प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने ही देश में सुख, शांति, संतुलन एवं सह-जीवन का अनुभव कर सकेगा और पलायनवादी सोच से बाहर आ सकेगा।

पर्यावरण

राजकुमार सिन्हा
लेखक बरगी बांध विस्थापित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

बिगड़ता पर्यावरण जैव-विविधता पर बढ़ा खतरा

'वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024' की रिपोर्ट में 180 देशों में भारत को 176वें स्थान पर रखा गया है। भारत का सबसे निचले स्थान पर होना मुख्य रूप से अकुशल भूमि-प्रबंधन और जैव-विविधता पर बढ़ते खतरों के कारण है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब संपूर्ण पारिस्थितिकी विनाश की संभावना के बारे में चर्चा करना जरूरी है, लगभग उसी संदर्भ में जैसे परमाणु हथियारों के आलोचकों ने अक्सर पूर्ण परमाणु विनाश की संभावना का उल्लेख किया है। हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, मानव स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ मानवीय संबंध के यांत्रिक दृष्टिकोण में उलझी हुई है, जो सीधे तौर पर पारिस्थितिक अनिवार्यता के विपरीत है। भारत की बात करें तो इंग्लैंड स्थित 'यूटिलिटी बिडर' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीस वर्षों में 6,68,400 हेक्टेयर जंगल देश ने खो दिया है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच वनों की कटाई की दर में भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, 'ग्लोबल फारेस्ट वाच' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने रिपोर्ट दी है कि भारत ने 2001 से 2023 के बीच 23300 वर्ग किलोमीटर वृक्ष-क्षेत्र खो दिया है। 'ग्लोबल फारेस्ट वाच' ने यह भी बताया है कि 2013 से 2023 तक 95 प्रतिशत वनों की कटाई प्राकृतिक वनों में हुई है।

मध्यप्रदेश वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1980 से अब तक सबसे ज्यादा वन-भूमि, 86330.52 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं के लिए खत्म हुई है, उसमें भी सबसे ज्यादा नर्मदा घाटी के बांधों से हुई है। अगस्त 2024 को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 'पिछले 10 वर्षों में विकास गतिविधियों के कारण 1,73,396 हेक्टेयर वनक्षेत्र नष्ट हो गया है।' उन्होंने दावा किया कि 2013 से 2023 के बीच 21,761 वर्ग किलोमीटर प्रतिपूरक वनरोपण से वन-क्षेत्र की भरपाई हुई है। बेंगलुरु के 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' के डाक्टर एमडी मधुसूदन ने बताया कि आमतौर पर नक्शे सार्वजनिक नहीं होते, परन्तु 'जियो स्पेशल डेटा नीति' के बाद 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के लिए नक्शे सार्वजनिक हुए। देहरादून स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग' ने 1999 से 2019 के दौरान असम के सोनीतपुर में 34,400 हेक्टेयर वनक्षेत्र कम होने की जानकारी दी थी, जबकि इसी दौरान 'फारेस्ट सर्वे रिपोर्ट' में वहां 33,800 हेक्टेयर वनक्षेत्र बढ़ा बताया गया। मधुसूदन के मुताबिक जब सोनितपुर के डिजिटल नक्शे को जूम किया गया तो पता चला कि जिस इलाके को फोरेस्ट दिखाया गया है, वह चाय बागान है।

तमिलनाडु के कोयंबटूर के वेलापरई में चाय बागानों को भी फोरेस्ट कवर दिखाया गया है। लक्षद्वीप का 95 फीसदी इलाका फारेस्ट कवर है, जबकि वहां नारियल के पेड़ हैं और उनके बीच घनी आबादी बसी है। दिलचस्प तो यह है कि जैसलमेर के मरुस्थली इलाके को फारेस्ट कवर दिखाया गया है, जबकि वहां रेगिस्तानी झाड़ियां थीं। दिल्ली के लुटियन-जोन का कुछ हिस्सा भी 'फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया' के नक्शे में फारेस्ट कवर है। 'सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट' (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण कहती हैं कि 'स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट- 2021' के मुताबिक देश में 1.6 लाख हेक्टेयर (0.2 प्रतिशत) वन क्षेत्र बढ़ा है। देश में 7.753 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि है जिस पर 5.166 करोड़ हेक्टेयर फारेस्ट कवर है। बचे 2.587 करोड़ हेक्टेयर (34 प्रतिशत) वन-भूमि का क्या हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं है।

विकास कार्य के लिए जंगल कट रहे हैं, उनके स्थान पर हुए पौधारोपण को जंगल मान लिया गया है। पर्यावरणविद एवं 'विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी' में 'जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र' के लीडर देबादित्यो सिन्हा का कहना है कि सिर्फ पौधारोपण करने से जंगल का निर्माण नहीं हो सकता। प्राकृतिक वनों में वनस्पतियों की कम-से-कम तीन परतें होती हैं, जिसमें सबसे नीचे आता है 'वन तल' जो कि मिट्टी एवं जडी-बूटियों से बना होता है। इसके बाद झाड़ियां और फिर आते हैं पेड़। वन-तल एवं झाड़ीनुमा वनस्पति की सबसे अहम भूमिका होती है। केवल पेडों की संख्या पर निर्भर रहना मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र की जटिल संरचना और प्राकृतिक संतुलन की उपेक्षा करता है। 'राष्ट्रीय वन नीति' का लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मैदानी क्षेत्रों में 33.3 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 66.6 प्रतिशत भूमि को वनाच्छादित करना है। भारत 17 विशाल जैव-विविधता वाले देशों में से एक है। यहां दुनिया की 12 फीसद जैव-विविधता है। यह समृद्ध जैव-विविधता पारिस्थितिकी संतुलन, पोषण-चक्र और जलवायु विनियमन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के 27.5 करोड़ लोगों की आजीविका को सहारा देती है, जो वन-संसाधनों पर निर्भर हैं। देश के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में 1,03,258 से अधिक जीव-जंतुओं और 55,048 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। जैव-विविधता भारत की जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन (मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 'लोक लेखा समिति' की रिपोर्ट के अनुसार 'पर्यावरण और वन मंत्रालय' 45000 पौधों और 51000 जानवरों की प्रजातियों की पहचान करने के बाबजूद जैव-विविधता संरक्षण के मोर्चे पर विफल रहा है। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बाद कन्याकुमारी तक जाने वाले 1600 किलोमीटर लंबे इलाके को 'पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला' कहा जाता है। वर्ष 2010 में पर्यावरणविद् प्रो. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित 'पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल' ने इस संपूर्ण क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का दर्जा दिया था और यहां सीमित खनन का पक्ष लिया था। हालांकि, पेड़ काटने, खनन और अतिक्रमण के कारण 'पश्चिमी घाट' के पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर पड रहा है। गोवा में 2007 से 2011 तक करीब पैंतीस हजार करोड़ रुपये का अवैध खनन किया गया। 'इसरो' के अध्ययन के अनुसार 1920-2013 में 'पश्चिमी घाट' का 35 फीसद क्षेत्र नष्ट हो चुका है। स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा छत्तीसगढ के हसदेव के जंगलों को बचाने के संघर्ष को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुर्खियां मिल चुकी हैं। 'केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय' की 'फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी' द्वारा 15 जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ में 'पारसा ओपन कास्ट कोल माइंस' को फारेस्ट क्लियरेंस दे दिया गया। आदिवासी बहुल सूरजपुर और सरगुजा जिले में स्थित यह क्षेत्र एक लाख सत्तर हजार हेक्टेयर में फैले 'हसदेव अरण्य' का हिस्सा है जो सघन वनों से आच्छादित है। इसी में से 841.538 हेक्टेयर जैव-विविधता से परिपूर्ण हिस्से को खनन के लिए दे दिया गया है, जबकि 2009 में 'पर्यावरण मंत्रालय' ने 'हसदेव अरण्य' को माइनिंग के लिए 'नो गो क्षेत्र' घोषित किया था। 'हसदेव अरण्य' में स्तनपायी जीवों की 34, सरीसृपों की 14, पक्षियों की 111 और मत्स्य वर्ग की 29 प्रजातियां हैं। इसी प्रकार वृक्षों की 86, औषधीय पौधों की 51, झाडी प्रजाति के पौधों की 19 और घास प्रजाति के पौधों की अनेक प्रजातियां यहां मौजूद हैं।

'भारतीय वन सेवा' के पूर्व अधिकारी अशोक कुमार शर्मा और अन्य लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' में किए गए संशोधनों को भारत के जंगलों के लिए 'मृत्यु की घंटी' बताया है। वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी बताते हैं कि धरती के 36 जैव-विविधता हॉट-स्पॉट में से चार भारत में हैं, लेकिन आज उन पर भी खतरा मंडराना रहा है। बढते शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और संसाधनों के दोहन से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा बढ़ रहा है। जैव-विविधता पर 'अंतर-सरकारी निकाय' (आईपीबीईएस) के अनुसार, पृथ्वी की सतह का तीन-चौथाई हिस्सा पहले ही मानव जाति के लालची उपभोग के कारण काफी हद तक बदल चुका है और दो-तिहाई महासागरों का क्षरण हो चुका है। भारतीय अर्थशास्त्री पवन सुखदेव ने अनुमान लगाया है कि जैव-विविधता की हानि की लागत प्रतिवर्ष 1.75 से 4 लाख करोड़ रुपये तक होती है। अक्टूबर 2024 को कोलंबिया के केली में आयोजित 16 वें 'संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता सम्मेलन' के बाद भारत ने वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक अपने स्थलीय, अंतर्देशीय जल एवं तटीय और समुद्री क्षेत्रों के कम-से-कम 30 प्रतिशत को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ कार्ययोजना शुरू की है। 'नेशनल बायो-डायवर्सिटी स्ट्रेटजी एण्ड एक्शन प्लान' के अनुसार भारत ने 2017-2018 से लेकर 2021-2022 तक जैव-विविधता सुरक्षा, संरक्षण और पुर्नस्थापन के लिए 32,200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आगामी 2029- 2030 तक जैव-विविधता संरक्षण के लिए अनुमानित वार्षिक औसत व्यय 81,664.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकृति संरक्षण पर होने वाले निवेश से क्या बदलाव आता है। (सप्रेस)

दूरगामी राजनीतिक सोच का एक आइडिया

कटाक्ष

राजेंद्र बज
लेखक व्यंग्यकार हैं।

जरा देखिए तो सही, कुछ वरिष्ठ राजनेताओं ने तो अपने दिवंगत समकालीन पर अनावश्यक टीका टिप्पणी कर किसी न किसी रंजिश का बदला लेने की ठान रखी है। आए दिन कोई न कोई पूर्व स्थापित शख्सियत के बारे में ऐसी-ऐसी छोड़ देते हैं कि जमाने से रुखसत हो जाने के बाद भी व्यक्तित्व एवं कृतित्व की राजनीतिक हत्या हो जाती है। वैसे राजनीति भी कुछ लोगों के लिए एक प्रकार से मनोरंजन का माध्यम है। कुछ दर्शक एवं पाठक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राजनेताओं के परस्पर आरोप-प्रत्यारोप के सिलसिले से एडवेंचर का सुकून मिला करता है। ये जीव गहन रोमांच से भरपूर होकर आनंदित हो जाया करते हैं।

दूरदर्शन की राजनीतिक तू-तू- मैं-मैं झगड़ेती वर्ग के लिए असीम आनंद की कारक सिद्ध होती रही है। इसके चलते किसी से बोलचाल होने पर वे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भांति कांव-कांव करने के गुर सीखते हैं। जब कोई एक अच्छा दूसरे अच्छे की खाल खींचता है... तो यह सिलसिला निरंतर परवान चढ़ते चला जाता है। ऐसी खाल-खिंचाई कुछ लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करती है। प्रिंट मीडिया में भी कुछ पाठक चटखारे ले लेकर आरोप-प्रत्यारोप का जायजा लिया करते हैं । वे इतने निष्णात हो चुके होते हैं कि हर किसी के किसी पर आरोप का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए ? इसका भी सहज अनुमान लगा लिया करते हैं।

दरअसल अब दर्शक व पाठक एक प्रकार से राजनीतिक थुक्का-फजीति के सिलसिले के चलते अपने निजी दुख भूल जाया करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यदि निकट भविष्य में चिकित्सक गण रक्तचाप के मरीज को दूरदर्शन की चकल्लस न देखने की सख्त हिदायत देते हुए मिले। सोचता हूं, राजनीति में काम करने के लिए मोटी चमड़ी होना चाहिए। लेकिन अब यह भी सोचने लगा हूं कि मुर्दे की चमड़ी भी चट्टान की भांति होना चाहिए।

क्योंकि मेरे जीवन काल तक तो सब ठीक-ठाक हो सकता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे मृत्यु पश्चात भी राजनीति में नहीं घसीटा जाएगा।और कोई जाने या नहीं जाने लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं? इसलिए डूबने के पहले कुशल तैराकी का परिचय दे देना चाहिए।

कभी-कभी आदमी के जाने के बाद भी उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की छीछालेदारी होने लगती है। इसलिए संभावना का अनुमान लगाने के उपरांत उसका जीते जी ही खंडन कर देना चाहिए। कम से कम प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से तो किसी को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। ताकि इस धरा पर अपने बाद अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए।. और आए भी तो इस धरा पर अपनी आत्मा भटकने से बच सकें। आजकल जमाना बड़ा खराब हो चला है, जब सामने वाला सामना नहीं कर पाए तो वह अवसर की तलाश में ही रहा करता है।

खैर, आदमी को हर हाल में अपने आप को शांत चित्त रखना चाहिए, लेकिन जरूरी यह भी है कि उसमें इतना सामर्थ्य हो कि आने वाली आपदा का बहादुरी से सामना कर सके। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीते जी कोई उनसे पंगा लेना नहीं चाहता। लेकिन उनके गुजर जाने के पश्चात मुखर हो उठता है। आमतौर पर राजनीति में कहां की खुन्नस कहां निकाल दी जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि गुजर जाने पर उठने वाले सवालों का जवाब जीते जी ही दे दिया जाए। यूं भी जिंदगी का कोई हिसाब किताब शेष नहीं रखना चाहिए। और तो और जमाने से बाय-बाय हो जाने के उपरांत भी सामने वाले का हिसाब चुकता करने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

रामविलास जांगिड़
लेखक व्यंग्यकार हैं।

जुमले तो रहेंगे, नेता आएंगे-जाएंगे

आसान भाषा में कहें तो जुमले 'वो बड़े-बड़े वादे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते।' देश की राजनीति में जुमले सबसे चमकीले गहने बने हुए हैं। राजनीति का पूरा संसार इन्हीं जुमलों पर टिका है। जुमला शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से अरबी से हुआ, जिसका मतलब होता है, 'एक समूह या संगठित बात'। पर हमारे नेताओं ने इसे एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचाया है- वादों के समूहों का ऐसा जाल जिसमें जनता उलझती ही जाए। जब कोई नेता माइक पकड़ता है और कहता है, 'हमारी सरकार आएगी तो सभी घरों के सब कमरों में रोशनी होगी, हर खेत में पानी का बंबा होगा, हर हाथ में फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी होगी।' जनता झूम उठती है, तालियां बजती हैं, लोग नारे लगाने लगते हैं। फिर चुनाव खत्म, तालियां खत्म और जनता फिर वही- अंधेरे में, खेत सूखे और हाथ खाली। इसे कहते हैं- 'जुमला।'

भारत में राजनीति और जुमलों का संबंध ऐसा है जैसे क्रिकेट और चौके-छक्के। कोई चुनाव आता है, तो जुमलों की गूंज हर नुक्कड़-चौराहे पर सुनाई देने लगती है। हर कोई नेता अपने मन के पिटारे से नया-नया जुमला निकालकर जनता पर फेंकता है। एक कहता है, 'हम तो हर वोटर को 5000 रुपए महीना देंगे', दूसरा कहता है, 'हम मुफ्त रोटी देंगे।' एक और आता है और कहता है, 'हम तो हाथों-हाथ सब कुछ मुफ्त दे देंगे!' अब जनता चकर गिन्नी खाकर सोचती है, 'अरे भाई! ये इतना सब फ्री में दे रहे हैं, तो हमें इन्हें चुनने में क्या हर्ज है?' लेकिन साहब! असली खेल तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। फिर ये नेता आपको बड़े प्यार से समझाते हैं, 'देखिए, चुनावी वादा तो था, पर सरकारी खजाना खाली है। थोड़ा धीरज रखिए, सब होगा।' ये धीरज जनता में चुनावों से चुनावों तक जारी रहेगा। जुमलों से हमारे समाज में विविधता में एकता जैसी भावना आ जाती है। हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय एक हो जाता है, जब एक नेता को चुनने के लिए जिसने सबसे बड़ा जुमला फेंका हो। नेताओं में कंपटीशन रहता है कि कौन सबसे बड़ा और नया जुमला फेंक मारे। चुनावों के बाद जब वादे हवाई हो जाते हैं, तो जनता फिर से पुराने मतभेदों पर लौट आती है, मानो कह रही हो, 'भाई, इस बार भी हमें चूना लग गया!' वैसे तीन शब्दों के षड्यंत्र चुनाव में पहले दो शब्द तो चूना ही आते हैं।

भारतीय संस्कृति में जुमलों की एक सुदृढ़ परंपरा है। हमारी दादी-नानी हमें कहानियां सुनाती थीं, वैसे ही हमारे नेता हमें चुनावी मौसम में वादों की कहानियां सुनाते हैं। गारंटी की लोरियां सुनाते हैं। जुमले अब चुनावी सांस्कृतिक अनुष्ठान बन चुके हैं। बाकी देश पढ़ाई, विज्ञान और शोध में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम विकास की गंगा बहाएंगे, देश को सोने का हाथी बना देंगे, और चांद पर चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी लगा देंगे, जैसे जुमलों का आनंद ले रहे हैं। चुनावी वक्त में हर गली-नुक्कड़, मोहल्ला-मकान 'जुमला शो' का मंच बन जाता है। जुमलों का इतिहास व भूगोल को देखा जाए तो स्पष्ट है कि राजनीति में इसकी महत्ता हमेशा बनी रहेगी। नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन जुमले सदाबहार रहेंगे। नेता हर बार इस जुमलेबाज़ी की कला में ज्यादा निपुण होते जाएंगे।

गीतों के माध्यम से दिलों पर राज करती रहेंगी शारदा सिंहा

इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजपुरी लोक साहित्य को अपने अनुपम योगदानों से वाली शारदा सिंहा हमेशा कालजई बनी रहेंगी। उनकी गायकी के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे विवाह का शुभ अवसर हो या छठ महापर्व का, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश समेत भारत के समस्त आंचलिक प्रदेशों में जब तक उनके गाए गीतों से घर-बाहर सर्वत्र गुजायमान नहीं हो उठता, तब तक रस्में पूरी नहीं होतीं और सबकुछ ही प्राय: अधूरा-सा प्रतीत होता है। देखा जाए तो शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज से बिहार के लोक संगीत को एक नई पहचान प्रदान की। वहीं, संगीत की दुनिया में उनके अतुलनीय योगदानों के लिए उन्हें 'पद्मश्री' तथा 'पद्मभूषण' से सम्मानित भी किया गया।

स्मृति शेष

चेतनादित्य आलोक

लेखक स्तंभकार हैं।

बिहार की प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिंहा का 05 नवंबर को देर शाम 72 साल की उम्र में निधन हो गया। आश्चर्य कि मूलत: छठ गीतों से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली शारदा सिंहा का देहांत भी छठ महापर्व के दौरान ही नहाय-खाय के दिन हुआ। बताया जाता है कि इसी वर्ष 21 सितंबर को 80 साल की आयु में ब्रेन हेमरेज से उनके पति ब्रज किशोर सिन्हा की मृत्यु हो जाने के बाद से ही वह बीमार रहने लगी थीं। शारदा सिंहा के निधन से भोजपुरी जगत् में एक ऐसा सूनापन पैदा हुआ है, जो कभी भरा नहीं जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजपुरी लोक साहित्य को अपने अनुपम योगदानों से वाली शारदा सिंहा हमेशा कालजई बनी रहेंगी। उनकी गायकी के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे विवाह का शुभ अवसर हो या छठ महापर्व का, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश समेत भारत के समस्त आंचलिक प्रदेशों में जब तक उनके गाए गीतों से घर-बाहर सर्वत्र गुजायमान नहीं हो उठता, तब तक रस्में पूरी नहीं होतीं और सबकुछ ही प्राय: अधूरा-सा प्रतीत होता है। देखा जाए तो शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज से बिहार के लोक संगीत को एक नई पहचान प्रदान की। वहीं, संगीत की दुनिया में उनके अतुलनीय योगदानों के लिए उन्हें 'पद्मश्री' तथा 'पद्मभूषण' से सम्मानित भी किया गया।

कलाकारों को बहुत सम्मान देती थीं

शारदा सिंहा को जानने वाले बताते हैं कि वह कलाकारों को बहुत सम्मान देती थीं। कई बार ऐसा देखा गया, जब वह रांची आकर गीत-संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करती थीं, तो साथी कलाकारों के साथ अत्यंत प्रेम भाव के साथ व्यवहार करती थीं। पटना इंस्टीट्यूट ऑफम्यूजिक के प्राचार्य तथा शास्त्रीय गायक डॉ. ओम प्रकाश नारायण भी मान चुके हैं कि शारदा सिंहा कलाकारों की बहुत कद्र करती थीं।

नर्तकी बनना चाहती थीं

शारदा सिंहा की इच्छा प्रारंभ में नर्तकी बनने की थी। उन्होंने एक नृत्य गुरु के समक्ष अपनी यह अभिलाषा प्रकट भी की थीं, लेकिन नृत्य गुरु ने उन्हें गायन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने की राय दी थी। नृत्य गुरु ने तब शारदा सिंहा से कहा था कि उनकी आवाज में जो कशिश है, वह गायन में अद्भुत निखार लाएगा। इसलिए उनके लिए गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है... और देखिए कि उस नृत्य गुरु की बातों को शारदा सिंहा ने सत्य साबित करते हुए गायन के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ ही दिया। अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए उन्होंने न केवल भोजपुरी, बल्कि मैथिली, मगही, बज्जिका, हिंदी आदि भाषाओं में भी अनेक प्रकार के लोकगीतों का गायन किया था। बताया जाता है कि करियर के शुरूआती दौर में एक बार उन्हें 'प्रयाग संगीत समिति' के आयोजन 'बसंत महोत्सव' में अपना हुनर दिखाने का जब अवसर मिला, तब प्रयाग में आयोजित उक्त कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसके बाद तो उनकी गायकी धीरे-धीरे मंजती ही चली गई। एक गायिका के रूप में उन्होंने आंचलिक लोक-संगीत को एक नया आयाम दिया।

बिहार कोकिला के रूप में विख्यात

लोकगीतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाली बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा 'बिहार कोकिला' के रूप में विख्यात् रही हैं। उनका जन्म 01 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिलांतर्गत हुलास गांव में हुआ था। गौरतलब है कि बचपन से ही घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनका रूझान गीत-संगीत की ओर हो गया था। बाद में जब उनका विवाह बेगूसराय जिला स्थित सिहमा गांव के मैथिली भाषा-भाषी ब्रज किशोर सिन्हा के साथ संपन्न हुआ, तब वहां पर उन्हें मैथिली लोकगीतों की परंपरा से अवगत होने का अवसर मिला। वह स्वयं मानती थीं कि अपने पैतृक घर यानी मायके और ससुराल दोनों जगहों पर संगीतमय माहौल होने के कारण संगीत के सुरों के प्रति उनका लगाव

धीरे-धीरे और गहरा होता चला गया। वैसे उन्होंने स्व. पं. सीताराम जी से शुरू शिष्य परंपरा के अनुसार शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसमें फूहड़पन का नामोनिशान तक नहीं मिलता है। उन्होंने सदा ही मर्यादाओं का पालन करते हुए गीतों का गायन किया। उनकी वेषभूषा भी समृद्ध भारतीय परंपरा के अनुरूप ही होती थी।

छठ गीतों से मिली पहचान

हालांकि वह अपने करियर के आरंभ में मैथिली लोकगीत गाती थीं, लेकिन शीघ्र ही जब उन्हें भोजपुरी में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला तो उन्होंने भोजपुरी में अपना नाम रोशन करने में देर नहीं लगाई। यहां तक कि उन्होंने बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान तो छठ गीतों से ही बनी थी। बता दें कि टी-सीरीज, टिप्स एवं एचएमवी सहित कई बड़े और नामचीन संगीत कंपनियों के लिए उन्होंने गीत गाए। इन कंपनियों के कुल नौ एल्बमों के लिए उन्होंने 60 से भी अधिक छठ गीत गाए थे।

हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत गाई

बिहार कोकिला के रूप में विख्यात् शारदा सिन्हा ने अपने पूरे करियर में बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए थे। इनमें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए 'तार बिजली से पतले' और 'हम आपके हैं कौन' के लिए 'बाबुल जो तुमसे पाया' तथा 'मैंने प्यार किया' के लिए 'कहे तोसे सजना' जैसे यादगार गीतों को अपने सुरों से सजाया, जो संगीत के क्षेत्र में उनकी दीवानगी और ऊंची रेंज की भी परिचायक हैं।

हाल ही में नया छठ गीत जारी

पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण शारदा सिंहा एम्स में भर्ती थीं। इसके बावजूद प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व से पूर्व नया छठ गीत जारी करने की अपनी परंपरा उन्होंने नहीं तोड़ी। बता दें कि शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा ने उनके प्रशंसकों के लिए एक ऑडियो सॉन्ग हाल ही में रिलीज किया था। उस ऑडियो के निर्माता स्वयं अंशुमान हैं, जबकि इस गीत को संगीतबद्ध किया है आदित्य देव ने और हृदय नारायण झा ने इसे लिखक है।

कुछ प्रमुख छठ गीत

'महिमा बा राउर अपार छठी मैया... !' भोजपुरी भाषा का यह अत्यंत लोकप्रिय छठ गीत शारदा सिन्हा ने 2003 में गाया था। इसके अलावा 2003 में ही उन्होंने मैथिली भाषा में इस गीत को भी गाया था- 'सकल जगतारिणी हे छठी मैया... !' इसी प्रकार, 'पहिले-पहिले हम कईनी, छठ मैया, बरत तोहार...' गीत उन्होंने 2016 में गाया था, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कर दिया। बताया जाता है कि इसी गीत ने देश के अतिरिक्त विदेशों में बसे भारतवंशी युवाओं को छठ महापर्व की महत्वपूर्ण परंपराओं से जोड़ने कार्य किया था। शारदा सिंहा का एक और लोकप्रिय छइ गीत 'हो दीनानाथ...' 1986 में जारी हुआ था, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति में सराबोर करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही, 'केलवा के पात पर उगलन सूरजमल झुके झुके...' गीत को भी उन्होंने 1986 में ही गाया था।

कुछ प्रमुख विवाह गीत

छठ गीतों की तरह ही शारदा सिन्हा के विवाह गीत भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने बेटी की विदाई के दर्द को इतनी खूबसूरती से अपने गीतों में उतारा है कि प्राय: यह गीत प्रत्येक विवाह में बजाया ही जाता है। 'बाबुल का घर छोड़कर...' गीत लोगों को इतना भावुक करने वाला है कि दुल्हन की विदाई के समय प्राय: इसे सुनकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। इसके विपरीत विवाह के अवसर पर हंसी-ठिठोली से भरपूर गीत 'सांवर-सांवर सुरतिया तोहार दुल्हा...' में दुल्हन की सखियां दूल्हे की खींचाई करती हैं। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके बोल और भाव अत्यंत मधुर होने के कारण यह लोगों के दिलों में रच-बस चुका है। इसी प्रकार, 'शिव से गौरी ना बियाहब...' गीत भी विवाह के मौके पर दूल्हे की खींचाई करते हुए दुल्हन पक्ष की महिलाएं गाती हैं। इसके अलावा 1977 में गाया गया 'दूल्हा धीरे-धीरे चलियो...' मंडप में दूल्हे के प्रवेश के समय गाया-बजाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है। (इतिश्री)

कटेंगे तो उपयोगी बनेंगे

वक्रोक्ति

सुरेश सौरभ

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मैं अक्सर जब कहीं मेहमानी में जाता हूं या किसी परीक्षा के लिए परीक्षक बनकर वाइवा लेने जाता हूं, तो वहां कटे हुए, छिले हुए फल जब खाने मिलते हैं, तो आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है। दिल बाग-बाग हो झूम जाता है, वैसे भी कटे हुए फल, कटा हुआ सलाद बहुत कम जगह ही देखने को, या खाने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर इसे गया-बीता प्रचलन लोग मानने लगे हैं, ज्यादातर लोग रेडीमेड मिठाइयां, चाट-पकौड़ी,नमकीन, नूडल्स, पिज्जा बर्गर आदि खाना-खिलाना आधुनिकता की निशानी और अपनी शान-ओ-शौकत समझने लगे हैं। क्योंकि काटने-छीलने में बड़ी झंझटें होतीं हैं, बड़ी मुसीबतें होतीं हैं, दरअसल काटने-छीलने से लेकर खिलाने तक की सही टाइमिंग का आवश्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर फल मेहमानों के आने से पहले काट-छील कर रख दिएं जाएं और मेहमान विलंब से आएं तो वह फल काले या मटमैले पड़ जाएंगे फिर न वह फल देखने में अच्छे लगते हैं और न खाने में।

एक बार मैं जब ससुराल गया तो वहां मेरी साली जी ने कहा-जीजू फल खाएं, तो काट दें। मैंने कहा-अभी नहीं खाएंगे थोड़ा रुक कर खाएंगे? तो उसने तपाक से कहा-जब खाना हो तो बेतकल्लुफ बता देना जभी काटेंगे, अगर पहले से ही काट-छील कर रख देंगे तो वह काले पड़ जाएंगे, बेस्वाद हो भी जाएंगे।

अत: मुझे अहसास हुआ कि डिजिटलकरण के इस अमृतकाल में, पढ़ी-लिखी महिलाएं ज्यादा जगरूक, और सशक्त होने लगीं हैं। यह हमारे देश के लिए बड़ी क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जा सकती है। यानि साली साहिबा को सही टाइमिंग पता है कि कब फल काटने-छीलने है, कब मेहमानों के सामने तश्तरी में सजाकर पेश करने हैं। मैंने इस सामान्य ज्ञान के लिए साली जी की मुक्त कंठ से ऐसे प्रशंसा की जैसे कई महीनों से इनकमिंग बंद पड़े मोबाइल को अचानक रिचार्ज कराने वाले सिम उपभोक्ता को संबंधित टेलीकाम कंपनियां करती हैं।

कुछ पशु-पक्षी कीट-पतंगें,कुछ वनस्पतियां उनके फल-फूल काट-काट खाते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, फिर उनके बीज, उनके परागकण जहां-तहां ले जाकर बिखराते हुए प्रकृति के नैसर्गिग सुषमा में श्रीवृद्धि करते रहते हैं। वैसे भगवान राम को कभी भिलनी शबरी ने अपनी कुटिया में अपने दांतों से काट-काट, चख-चख, मीठे-मीठे बेर बड़े प्रेम से खिलाए थे। राम ने तो वह बेर शबरी के प्रेम वश, प्रेम से खा लिए थे, लेकिन जब राम जी ने वही बेर लक्ष्मण जी को खाने तो दिये तो उन्होंने न खाकर पीछे फेंक दिए और भविष्य में लक्ष्मण जी के फेंके वहीं शबरी के जूठे बेर, उनके लिए द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बने। नवजीवन बने। कभी शबरी के झूठे बेर लक्ष्मण जी के जीवन रक्षक बनेंगे। यह किसी ने कब सोचा था। प्रेम के जूठे बीज भी संजीवनी बनते हैं, नफरत से कटे-बंटे बीज-बेर बोते लोगों के नसीब में एक दिन सिर्फ नफरत का वैमनस्वता का ही फल हाथ लगता है। सब्जी हो, फल हो या कोई अनाज हो, या कोई अन्य ठोस गैस या द्रव पदार्थ वाली चीजें पहले मशीनों में कटती हैं, फटती हैं, छनती हैं फिर आवश्यकतानुसार नये रूप में एकाकार हो कर हमारे सामने पेश हो जातीं हैं। हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो जाती हैं। साइंस वाले भी कहते हैं कि सभी पदार्थ अपना रूप बदलते रहते हैं, नष्ट कभी नहीं होते, फिर चाहे वह जले, कटे, फटे या रंग बदल कर उड़े।

देसी खिलौनों की खत्म होती चमक

पारंपरिक

अमरपाल सिंह वर्मा

स्वतंत्र लेखक

पंजाब के एक छोटे से कस्बे धनौला में पारंपरिक रूप से लकड़ी के खिलौने बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों की आर्थिक बदहाली परेशान करने वाली है। दशकों से ये कारीगर बच्चों के लिए लकड़ी के ट्रैक्टर, बस, कम्बाइन, ट्रॉली आदि बनाते आ रहे हैं। पहले हजारों घरों के बच्चे इन खिलौनों से खेलकर खुश होते थे जिससे इन कारीगरों के बच्चों के भरण-पोषण का रास्ता खुलता था, पर अब हालात बदल रहे हैं। धनौला के कारीगरों के बनाए खिलौने बड़ी कंपनियों के बनाए अति-आधुनिक खिलौनों से होड़ में पिछड़ रहे हैं। इसका नतीजा इन कारीगरों के परिवारों की तंगहाली के रूप में सामने है।

बरनाला और संगरूर के बीच बसे खिलौनों के लिए मशहूर धनौला के कारीगरों की यह हालत उस समय है, जब भारतीय खिलौना बाजार को संभावनाओं से भरपूर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश में खिलौनों का बाजार फल-फूल रहा है। 'केंद्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय' की ओर से इस साल प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच हमारे देश के खिलौना उद्योग में तीव्र गति से उन्नति हुई है।

यह रिपोर्ट दावा करती है कि एक ओर जहां हमारे देश से खिलौनों के निर्यात में 239 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर आयात में 52 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह भी दावा है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान से हमारे देश का खिलौना उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खिलौना उद्योग में हमारी प्रगति से चीन को झटका लगा है।

जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है, भारतीय खिलौना बाजार में असीम संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के बूते वह खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और उद्यमियों को अपनी ओर खींच रहा है।

यह भी दावा है कि वर्ष 2024 में हमारे देश का खिलौना बाजार 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, लोग अपने बच्चों के लिए अधिक संसाधन जुटा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप खिलौनों पर खर्च बढ़ रहा है।

इन आंकड़ों से हम देश के खिलौना बाजार में बरस रहे पैसे का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। देश-विदेश में भारत निर्मित खिलौनों की मांग बढने से जहां खिलौना निर्माताओं की चांदी हो गई है, वहीं खुदरा विक्रेता को भी फायदा मिल रहा है। यकीनन, खिलौना बाजार की इस प्रगति की हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुशी की इस बेला में धनौला कस्बे के खिलौने बनाने वाले कारीगर उदास क्यों हैं?

यह सही है कि बदलते परिवेश में बच्चों की पसंद बदल रही है। वे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को तरजीह देते हैं। चीन निर्मित खिलौनों ने बच्चों की पसंद को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन क्या ऐसे में पारंपरिक कारीगरों को उपेक्षित छोड़ दिया जाना चाहिए? अकेले पंजाब के धनौला में ही सैकड़ों कारीगर हैं, जिनके परिवारों की रोजी-रोटी लकड़ी के खिलौने बेचकर ही चलती है। पूरे देश में तो ऐसे पारंपरिक कारीगरों की संख्या लाखों में होगी, जिनकी कला प्राचीन भले ही है, लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये कारीगर हमारी धरोहर हैं, इन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए।

सरकारी दावा है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान घरेलू खिलौना उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, स्थानीय रूप से निर्मित खिलौनों की ओर रूझान बढ़ाता है और आयात पर निर्भरता कम करता है। अगर यह सच है तो धनौला के स्थानीय कारीगरों के बनाए खिलौने क्यों पिछड़ रहे हैं? क्यों धनौला के कारीगर खिलौने बनाने का काम छोडने पर मजबूर हो रहे हैं? उनके बनाए खिलौनों की ओर रूझान बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है?

'केंद्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय' की रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, खिलौनों की मांग बढ़ेगी और खिलौना बाजार और फले-फूलेगा, लेकिन खुशी के इस मौके का आनंद मनाने का मौका दूरदराज के छोटे कारीगरों को भी तो मिलना चाहिए। धनौला जैसी छोटी जगहों के कारीगरों को यह कहकर तो उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता कि उनके खिलौने 'आउटडेटेड' हो गए हैं। सरकार को ऐसे गरीब कारीगरों की भी सुध लेनी चाहिए। अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो ये कारीगर अपने पारंपरिक खिलौनों को आधुनिक शैली में ढाल सकते हैं। उन्हें इस बारे में ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा सकती है। 'मुद्रा लोन' जैसी योजनाओं का लाभ ऐसे छोटे कारीगरों को भी तो मिलना चाहिए। जब सरकारी अधिकारी इन कारीगरों की बस्तियों तक पहुंच कर उनका हाल पूछेंगे तो हो सकता है कोई रास्ता निकल ही आए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? (सप्रेस)

प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर ढांचे की जरूरत

शिक्षा

ममता

इसी सप्ताह राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित कौशल व उद्यमिता विभाग के साथ निवेशकों ने 28 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के एमओयू साइन किया. इससे सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बेहतर डाइनिंग हॉल तैयार करने में मदद मिलेगी. साथ ही स्कूली छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं, प्रदेश में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के विकास, स्कूलों में ब्लॉक लेवल पर खेल के स्टेडियम, ऑनलाइन परीक्षा सुविधा केंद्रों की स्थापना और लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी. राज्य सरकार के इस पहल से स्कूलों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है. लेकिन शिक्षा की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है.

राज्य के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां प्राइमरी स्तर पर संचालित सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी है. अजमेर स्थित नाचनबाड़ी गांव ऐसा ही एक उदाहरण है. जिला मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर घूघरा पंचायत स्थित इस गांव में अनुसूचित जनजाति कालबेलिया समुदाय की बहुलता हैं. पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार गांव में लगभग 500 घर हैं. यहां संचालित एकमात्र प्राथमिक विद्यालय में पूरी तरह से बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. मात्र 2 कमरों में संचालित इस स्कूल में करीब 45 बच्चे पढ़ते हैं. इस संबंध में गांव के एक अभिभावक सदानाथ कहते हैं कि उनकी दो बेटियां हैं और दोनों गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाती हैं. लेकिन स्कूल में सुविधाओं की कमी के कारण वह अक्सर स्कूल जाने से मना करती हैं. वह कहते हैं कि स्कूल में शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है. वह बच्चों के इस्तेमाल के लायक नहीं है. इसके अतिरिक्त स्कूल में पीने के साफ़ पानी की भी कमी है. एक हैंडपंप लगा हुआ है जिससे अक्सर खारा पानी आता है. जिसे पीकर बच्चे बीमार हो जाते हैं. वह कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों की बुनियाद को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है. लेकिन जब सुविधाओं की कमी के कारण बच्चे स्कूल ही नहीं जायेंगे तो उनकी बुनियाद कैसे मज़बूत होगी? उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आएगी.

एक अन्य अभिभावक 55 वर्षीय भेरुनाथ कालबेलिया बताते हैं कि उनके समुदाय में पहले की अपेक्षा शिक्षा की स्थिति सुधरी है लेकिन बालिका शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत कम है. लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के प्रति बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं. गांव के प्राथमिक विद्यालय में लड़कियां पांचवीं तक पढ़ती हैं. लेकिन स्कूल में सुविधाओं की कमी के कारण पढ़ाई के प्रति उनकी दिलचस्पी भी कम हो जाती है. वह बताते हैं कि पांचवीं तक पढ़ाने के लिए स्कूल में दो शिक्षक हैं. जिन पर पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के विभागीय कार्यों को भी समय पर पूरा करने की ज़िम्मेदारी होती है. यही

कारण है कि वह पढ़ाने से अधिक कागज़ी कार्रवाइयों को पूरा करने में अधिक समय देते हैं. जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है. उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है. भेरुनाथ कहते हैं कि पांचवीं से आगे उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को घूघरा जाना होता है. जो नाचनबाड़ी से करीब दो किमी दूर है. लेकिन गांव के प्राथमिक स्कूल में ही शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है तो बच्चे आगे की पढाई में कैसे दिलचस्पी लेंगे? भेरुनाथ की 15 वर्षीय बेटी पूजा 9वीं कक्षा की छात्रा है. वह बताती है कि गांव में उसके उम्र की करीब 13 किशोरियां है. जिनमें केवल 6 लड़कियां ही आगे की पढ़ाई के लिए घूघरा जाती हैं. हालांकि सभी ने पांचवीं तक गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की, जहां सुविधाओं की काफी कमियां थीं. वह कहती है कि बुनियादी स्तर पर कमज़ोर शिक्षा के कारण हमें आगे की पढ़ाई में काफी मेहनत करनी पड़ रही है.

वहीं छोटूनाथ बताते हैं कि स्कूल में शिक्षक नियमित रूप से आते हैं लेकिन अक्सर विभाग के कागज़ी कामों में व्यस्त होने के कारण वह बच्चों को पढ़ाने में बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं. जिससे बच्चे पढ़ने की जगह स्कूल में केवल समय काट कर आ जाते हैं. इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित हो रही हैं. गांव के अधिकतर अभिभावक नाममात्र के शिक्षित हैं. इसलिए वह अपने बच्चों को घर में भी पढ़ा नहीं पाते हैं. इन कमियों की वजह से नाचनबाड़ी गांव के बच्चों की बुनियादी शिक्षा ही कमज़ोर हो रही है, जिससे उन्हें आगे की कक्षाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अधिकतर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं. वह कहते हैं कि इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ता है. बुनियाद कमज़ोर होने के कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं में उन्हें मुश्किलें आती हैं. छोटूनाथ बताते हैं कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी को मिलाकर इस स्कूल में पांच पद खाली हैं. यदि इन्हें भर दिया जाए तो शिक्षक पूरी तरह से बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं. इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी.

गांव के सामाजिक कार्यकर्ता वीरमनाथ कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के प्रभावित होने के कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह इन स्कूलों में कई वर्षों तक शिक्षकों के पद खाली रहते हैं. जिसके कारण स्कूल में मौजूद एक शिक्षक के ऊपर अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों को पढ़ाने और समय पर सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी तो होती ही है साथ में उन्हें ऑफिस का काम भी देखना होता है. बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील और अन्य ज़रूरतों से संबंधित विभागीय कामों को पूरा करने में ही उनका समय निकल जाता है. जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है. वह कहते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में गांव के अधिकतर आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद कमजोर परिवार के बच्चे ही पढ़ने आते हैं. जो परिवार आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं. वीरमनाथ कहते हैं कि पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी पदों को मिलाकर करीब एक लाख से अधिक पद खाली हैं. जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द भरने की जरूरत है. इन खाली पदों के कारण शिक्षा कितना प्रभावित हो रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. हालांकि जिस प्रकार से राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है इससे आशा की जानी चाहिए कि जल्द ही इन कमियों को दूर कर लिया जाएगा.

इसी सप्ताह केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के छात्रों को आर्थिक मदद देना है ताकि पैसे की तंगी की वजह से वह उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए. यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा. शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम मील का पत्थर साबित होगा. लेकिन सबसे पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का पहला कदम होता है. ऐसे में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं से लैस कर इस कदम को मज़बूत बनाया जा सकता है. (चरखा फीचर्स)

कृषि मंडी में अव्यवस्था के विरोध में व्यापारियों ने रोकी खरीदी

समझाईश के बाद माने, दो घंटे नीलामी हुई प्रभावित

बैतूल। कृषि मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते व्यापारियों ने शुक्रवार खरीदी बंद कर दी। व्यापारियों का आरोप था कि मंडी में अव्यवस्था फैली है। इससे व्यापारी, किसान दोनों परेशान है। मंडी में बिगड़ी व्यवस्था की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक निलय डागा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंडी के अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। पूर्व विधायक निलय डागा ने बताया कि मंडी में बहुत अव्यवस्था है। यहां उपज रखने के लिए शेड फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं भी उपज रख दी जा रही है। ऐसे में कहां से माल की नाप होगी, वाहन कैसे निकलेंगे। मंडी में आने वाला माल तुल नहीं रहा है। गौरतलब रहे कि मंडी में इस समय मक्का व अन्य कृषि उपज की बंपर आवक हो रही है। जिससे यहां किसानों की उपज रखने के लिए जगह नहीं है। मंडी में सभी जगह उपज रखने के लिए अलग अलग उपज के लिए अलग-अलग स्थान तय है। लेकिन आवक बढ़ने से यह व्यवस्था बिगड़ गई। हालांकि समझाइश के बाद व्यापारियों ने खरीदी शुरू की। इधर मंडी सचिव शीला खातरकर ने बताया कि नीलाम चालू कर दिया गया है। रात को आए कुछ किसानों ने जल्दबाजी में उपज गलत जगह डाल दी थी। उसे उठवा लिया गया है। व्यवस्था बनाई जा रही है।

गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 11 नवंबर को बैतूल में निकलेगा विशाल नगर कीर्तन

चार साहिबजादे इंटरनेशनल गतका का प्रदर्शन रहेगा विशेष आकर्षण

बैतूल। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानण होआ। महान संत और गुरु श्री गुरुनानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बैतूल शहर में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन होने जा रहा है। सोमवार, 11 नवंबर 2024 को दोपहर 1 बजे से बैतूल के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गंज से इस नगर कीर्तन का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का संगम गुरुद्वारे में जुटेगा, और पूरे नगर में गुरुनानक नाम लेवा संगत की गूंज सुनाई देगी। नगर कीर्तन की विशेषता यह है कि इस बार इसमें चार साहिबजादे इंटरनेशनल गतका दल, आगरा से विशेष तौर पर आ रहा है। नगर कीर्तन का मार्ग गुरुद्वारा (गंज) से प्रारंभ होकर भगतसिंह चौक, कांति शिवा चौक, पोला चौक (मस्जिद चौक), एचडीएफसी बैंक चौक, राजू खंडेलवाल निवास के समीप, सिंधी गुरुद्वारा, सोबेग सिंह साहनी मेडिकल के सामने से होते हुए गुप्ता मॉल, गंज शनि मंदिर, गंज बस स्टैंड और फिर भगतसिंह चौक से होकर गुरुद्वारा वापस लौटेगा। आयोजनकर्ताओं द्वारा बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था भी की गई है ताकि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। संगत की सेवा में समर्पित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, बैतूल द्वारा नगर कीर्तन के पश्चात शाम 7 बजे सभी संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। इस पावन अवसर पर सभी संगतों से निवेदन किया गया है कि वे इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं।

जावरा में गांव के सभी बुजुर्गों का हुआ सम्मान

न्यू लक्ष्मी मण्डल ने किया कार्यक्रम का आयोजन

बैतूल। आठनेर ब्लॉक के ग्राम जावरा में परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी न्यू लक्ष्मी मण्डल (बजरंग मंदिर) जावरा द्वारा बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के सभी बुजुर्गों को अंग वस्त्र और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया, और उनसे आशीर्वाद लिया गया। साथ ही, मां लक्ष्मी की महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण कर गांववासियों ने इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। इस कार्यक्रम में भाजपा आठनेर नगर मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री कृष्णा गायकी, क्षत्रिय लोन्हारी कुंबी समाज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष पूनाजी कापसे, गिरधर पटेल, और गुणवंत पांसे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोवर्धन राने ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान हमारे समाज का दायित्व है और यह गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठजनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि और बुजुर्गों का अनुभव मिलकर गांव के विकास को नई दिशा देगा। श्री राने ने कहा कि युवा वर्ग और वरिष्ठजन एक-दूसरे की गरिमा बनाए रखकर जावरा को आदर्श गांव बना सकते हैं। भाजपा जिला मंत्री कृष्णा गायकी ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों के सम्मान को गर्व का विषय बताया। क्षत्रिय लोन्हारी कुंबी समाज के अध्यक्ष पूनाजी कापसे ने कहा कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों को और भव्य रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में न्यू लक्ष्मी मंडल के अध्यक्ष अडलक, उपसरपंच इन्द्रदेव कोसे, निलकंठ वंजारे, आचार्य धोटे, आयुष पंडाग्रे, सहादेव पंडाग्रे, सुखदेव सराटकर के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी, माताएं और बहनें उपस्थित रहीं।

अनदेखी : जालियां चोरी होने के बाद नपा ने नहीं किये दूसरे प्रयास

परिणाम : गंदे पानी के साथ प्लास्टिक और कचरा पहुंच रहा माचना नदी

जल प्रदूषण रोकने नगरपालिका नहीं कर रही कोई प्रयास, जलीय जीवों के जीवन पर पड़ सकता है संकट, एक बालक की नाली में बहने से हो चुकी है मौत

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर की नालियों में बहने वाले कचरे को रोकने के लिए नगरपालिका ने ऑस्ट्रेलियन पैटर्न की जालियां लगाई थी, ताकि कचरा बहकर नदी तक न पहुंचे, किन्तु यह जालियां चोरी हो गई। दोबारा नगरपालिका ने इस दशा में कोई काम नहीं किया। यदि जाली लगी होती तो हाल ही में एक बच्चे के नाली में बह जाने और फिर नाले में जाकर डूब जाने जैसी घटना नहीं होती। जालियां यहां पर लगी होती तो यह बच्चा यहां पर फंस जाता और बच जाता। लेकिन जालियां नदारद होने से ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नगरपालिका ने नालों पर जगह-जगह ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पर जालियां लगाकर नदी तक पहुंचने वाले कचरे को रोकने का प्रयास किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो प्लास्टिक सहित अन्य बड़ा कचरा नदी में पहुंचकर पानी को प्रदूषित कर रहा है, उसे नालों में ही रोका जा सके। इसके लिए शहर के सदर, टिकारी, गंज अंडरब्रिज के समीप की जगह पर जालियां लगाई गयी थी। जिसमें से गेंदा चौक नाले की जालियां गायब मिली। यहीं हाल आजाद वार्ड से होते हुए आर्यपुरा कंपनी

गार्डन से गुजरने वाले नाली पर भी देखी गई, यहां भी कंपनी गार्डन की पुलिया के नीचे जालियां लगाई गयी थी। गंज में रेलवे अंडर ब्रिज के समीप के नाले में भी जालियां भी नदारद मिली। परिणाम शहर की नालियों से होकर कचरा नालों के माध्यम से माचना नदी में पहुंच रहा है। जिससे नदी का प्रदूषण बढ़ने लगा है।

माचना में मिलते हैं शहर के अधिकांश नाले- शहर का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि वार्डों की नालियों से पानी होते हुए नालों के जरिये सीधे माचना में खुलता है। हर दिन करोड़ों लीटर गंदा पानी यहां पहुंचता है। इस पानी में बहने वाले प्लास्टिक और कचरे को नदी में मिलने से रोकने के लिए लगभग 4 साल पहले नगरपालिका ने ऑस्टेलियन ड्रेनेज सिस्टम की तर्ज पर मजबूत जालियां लगवानी शुरू की थी। यह जालियां और इसमें लगी लोहे की रिंग गायब हो गये। इसके बाद नपा ने जलप्रदाय चैंबरों पर लगने वाले लोहे के कटघरों जैसे लॉक सिस्टम लगाकर दोबारा जालियां लगाने की प्लानिंग की थी। लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ है, अब शहर का पूरा प्लास्टिक नालियों और नालों को जाम कर रहा है। कचरा नालियों को चोक कर रहा है। प्लास्टिक फंसने के कारण पानी निकासी की समस्या बढ़ रही है।

शहर से रोजाना निकलता है 4 करोड़ लीटर गंदा पानी- शहर में 27 हजार मकान हैं। इन मकानों से रोजाना 4 करोड़ लीटर गंदा पानी निकलता है जो कि नालियों के जरिए होता हुआ बड़े नालों में जाता है और ये नाले माचना नदी में खुलते हैं। शहर का अधिकांश ड्रेनेज सिस्टम हाथी नाले पर टिका है। हाथी नाला शहर का सबसे बड़ा और लंबा नाला है। इस नाले में ही देखे तो बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा दिखाई देगा, जो नालियों के जरिए पहुंचता है। नपा ने पानी फिल्टर करने के लिए हाथी नाले पर गंज अंडरब्रिज के समीप ड्रेनेज वॉटर फिल्टर प्लेटफॉर्म बनाया था। केवल एक जगह यह प्लेटफार्म बना था, यहां पर चार जालियां लगाई गयी थी। यह चारों जालियां नदारद हैं। इस कारण पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा है यहां से प्लास्टिक और थर्माकोल माचना तक जा रहा है।

कचरा पहुंचने से गंदगी से पट रही नदी - जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण शहर की नदी गंदगी से पटती जा रही हैं। नदी के प्रदूषण को रोकने स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कारगर उपाये तक नहीं किये जा रहे है। यहीं वजह है कि नदी के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जिससे पानी के प्रदूषित होने की संभावना और भी बढ़ गई है। यदि नदी में प्रदूषण की और मात्रा बढ़ी तो जलीय जीव-जंतुओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन को कम से कम गंदे पानी और कचरे को नदी में जाने से रोकने के उपाये करने चाहिए, ताकि नदी का जल प्रदूषित न हो, किन्तु नगरपालिका इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। जिससे शहर के लोगों में नाराजगी बनी हुई है।

इनका कहना है - कहां-कहां जालियां लगाई गई थी, इसके बारे में जानकारी ली जायेगी और दोबारा जालियां लगवाने का प्रयास करेगे। वैसे ड्रेनेज सिस्टम के नालो और बड़ी नालियों में जालियां होना चाहिए, जिससे बड़े कचरे के साथ प्लास्टिक रोका जा सके।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका, बैतूल

भगवान सहस्त्रबाहु की वीरगाथा से बच्चों को मिली प्रेरणा

तपश्री ज्ञान मंदिर शाला में भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पर विशेष प्रतियोगिता का आयोजन

बैतूल। कलचुरी कलार समाज के तत्वाधान में भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती के उपलक्ष्य में बैतूल के शैक्षणिक संस्थान तपश्री ज्ञान मंदिर शाला में एक विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान सहस्त्रबाहु का जन्मोत्सव, दीप प्रज्ज्वलित कर और छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर विधिवत मनाया गया। विद्यार्थियों के संग सहस्त्रबाहु की आरती कर महापुरुषों की गाथाओं से उन्हें प्रेरणा प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान दीप मालवीय ने भगवान सहस्त्रबाहु की वीरता का स्मरण कराते हुए कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु ने नर्मदा नदी का वेग रोककर असाधारण साहस का परिचय दिया। दीप मालवीय ने विद्यार्थियों को सहस्त्रबाहु की जीवन गाथा से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इसके बाद महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों को कॉपी, किताब, पेन, और पेंसिल उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निमिष मालवीय और शैलेंद्र बिहारिया ने बच्चों को महापुरुषों की गाथाएं सुनाईं, जिन्होंने समाज में नई परंपराएं स्थापित कीं और जनकल्याण के लिए अनगिनत कार्य किए। मुख्य अतिथियों ने बताया कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज और देश के लिए महान कार्य किए, वे सदैव हमारी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। कार्यक्रम में बच्चों ने महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में वीरता और संकल्प की भावना को जागृत करने का संकल्प लिया।

किसानों को खाद का सुचारू रूप से वितरण किया जाए

खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करें

बैतूल। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे और विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख तथा कलेक्टर बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन की उपस्थिति में कृषि एवं कृषि संबद्ध विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक बैतूल श्री खंडेलवाल द्वारा वर्तमान रबी मौसम 2024-25 में जिले में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप संचालक कृषि बैतूल द्वारा अवगत कराया गया कि जिले की सहकारी संस्थाओं तथा निजी उर्वरक केन्द्रों में यूरिया-13940 मे. टन, एस.एस.पी.-7268 मे. टन, डीएपी-2397 मे. टन तथा पोटास-1194 मे. टन एवं एनपीके-2040 मे. टन इस प्रकार कुल 26839 मे0टन उर्वरक की उपलब्धता है। विधायक श्री खंडेलवाल ने निर्देश दिए कि किसानों को खाद का सुचारू रूप से वितरण किया जाए,जिन उर्वरक विक्रय केन्द्रो पर उर्वरक की उपलब्धता विक्रय से कम हो रही है। उसकी मॉनिटरिंग की जाकर प्राथमिकता से उर्वरक उपलब्ध कराएं। खाद की कालाबाजारी न हो यह सुनिश्चित करें। खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। बताया गया कि जिले में आगामी बुआई के लिए डीएपी के कमी न हो इसके लिए 2 रैक डीएपी/एनपीके रैक की मांग भेजी जा चुकी है। जिसमें आई पी एल डीएपी की रैंक प्राप्त होंगी। विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे द्वारा सहकारी संस्थाओ व निजी उर्वरक विक्रेता केन्द्रों पर बुआई सीजन में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। बैठक में डीएपी के विकल्प के तौर पर एनपीके एवं एस.एस.पी. के उर्वरक को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गये विशेष पोस्टर तथा पेम्पलेट का अवलोकन भी विधायकगणों को कराया गया है। विधायक मुलताई श्री देशमुख द्वारा उर्वरकों में टेंगिग न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र में नरवाई न जले तथा धान की कटाई के बाद सीधे सुपर सीडर / हेप्पी सीडर से चना की बुआई के सबंध में बैठक में जानकारी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि जिले में अभी तक 309 एकड़ क्षेत्र में सुपर सीडर से सीधी बुआई कर नरवाई को खेत में मिलाने का कार्य किया जा चुका है। जिला कलेक्टर बैतूल द्वारा लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में लिए जाने के निर्देश भी समीक्षा बैठक में दिए। विधायक श्री खंडेलवाल ने बैठक में जल संसाधन विभाग को सिंचाई से पूर्व नहरों की मरम्मत और साफ सफाई का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। एमपीईबी का निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का आपूर्ति सुचारू रूप से की जाएं। विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। जले हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र बदले जाएं। उन्होंने पीएचई विभाग को निर्देश दिए कि पूर्ण हुई नल जल योजनाओं को शीघ्र हैंडोवर कराएं। विधायक आमला डॉ पंडाग्रे ने उद्यानिकी विभाग को निर्देश दिए की विभागीय अमले को सक्रिय कर विभाग अंतर्गत बनाए गए शेडनेट का सदुपयोग कराएं।

पारिवारिक कार्यक्रम में गया था परिवार, चोरों ने लगा दी सेंध

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम कामथ में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। फरियादी राजेन्द्र बोडखे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने परिवार के साथ गुरुवार को करीब 10.15 बजे अपने बड़े पिताजी गुलाबराव बोडखे के तेरहवीं के कार्यक्रम में ग्राम पारडसिंगा गए थे। उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया हुआ था। शाम के करीब 4.40 बजे, घर के सामने रहने वाले सुरेश माकोड़े ने फोन पर सूचना दी कि उनके घर का गेट खुला हुआ है। राजेन्द्र और उनके परिवार ने तुरंत घर लौटने पर देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। उनके बेडरूम और दूसरे कमरे की आलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। चोरों ने बेडरूम की आलमारी से 3 सोने की पोत,

3 लेडिस सोने की अंगूठियां, 3 सोने की चेन, 4 सोने की अंगूठियां, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 10 चांदी की चेन, बच्चों के 6 जोड़ी चांदी के कड़े, 3 छोटी चांदी की पायल, सोने की एक जोड़ी झुमकी और 2 जोड़ी झाले, तथा 98 हजार नकद रुपए चुरा लिए। फरियादी ने तत्काल 100 डायल कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर श्रीराम मंडावी को जांच सौंपी गई है।

कलेक्टर ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत 12 हितग्राहियों को किया लाभान्वित

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत जिले के 12 हितग्राहियों को 20 लाख की राशि का भुगतान कर उन्हें लाभान्वित किया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उप संचालक ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर 2 लाख प्रोत्साहन राशि तथा युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर संयुक्त रुप से 1 लाख प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सारणी पाथाखेडा निवासी श्रीमती काजल पति दीपक कापसे को 2 लाख रूपए, घोड़ाडोंगरी पाढर बुजुर्ग निवासी हिमांशु मालवीय पत्नी श्रीमती ज्योति को 2 लाख, जैतापुर रतनपुर निवासी श्रीमती कंचना साहू पति ओमप्रकाश को 2 लाख, भैंसदेही शिवकुंड निवासी नीतेश भलावी श्रीमती कलवंती को 1 लाख, भीमपुर चिखली गुडरिया निवासी कैलाश पांसे पत्नी श्रीमती प्रमीला को 1 लाख, प्रभातपट्टन सिरडी निवासी विजय सातनकर पत्नी श्रीमती सविता को 1 लाख, आमला कमलेश्वरा निवासी दीपक साहू पत्नी श्रीमती त्रिवेनी को 1 लाख की राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया है। इसी प्रकार बैतूल थावडी निवासी कृष्णा पत्नी श्रीमती लक्ष्मी धुर्वे को 2 लाख, घोडाडोंगरी आमढोह निवासी श्रीमती किर्ती माझी पति मनोज को 2 लाख, भैंसदेही सिरजगांव निवासी मंगल उईके पत्नी श्रीमती सलिया को 2 लाख, भीमपुर कामथमाल निवासी कृष्णा भुसुमकर पत्नी श्रीमती सोमती को 2 लाख तथा चिचोली असाडी निवासी सुंदर उईके पत्नी श्रीमती नीलमणी को योजना के तहत 2 लाख की राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया है।

आमला के वार्ड क्रमांक 12 में 3 लाख 6 हजार 703 रुपए की लागत से होगा प्रोफाइल टीन शेड निर्माण कार्य

बैतूल। आमला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 12 में 3 लाख 6 हजार 703 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति से निर्माण कार्य किए जाएगे। जारी आदेश के अनुसार आमला के वार्ड क्रमांक 12 में डॉक्टर सरदार के घर के समीप प्रोफाइल टीन शेड निमार्ण कार्य किया जाएगा। इसमें विधायक डॉ.पंडाग्रे की स्वेच्छानुदान निधि 2 लाख रूपए तथा नगर पालिका द्वारा 1 लाख 6 हजार 703 रूपए वहन किया जाएगा। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्माण एजेंसी नगर पालिका परिषद सारनी को योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

जिले में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए लैंड बैंक बढ़ाया जाएगा

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में जनप्रतिनिधियों उद्योगपतियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित

बैतूल। नर्मदापुरम संभाग अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के संभागीय आईटीआई में 7 दिसंबर 2024 को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बैतूल जिले में औद्योगिक विकास की गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, विधायक आमला डॉ.योगेश पंडाग्रे, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख तथा कलेक्टर बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन सहित एमपीआईडीसी और उद्योग विभाग के अधिकारियों तथा

उद्योगपतियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले में व्यापार व्यवसाय और निवेश को प्रोत्साहन मिले इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों उद्योगपतियों और अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की और सुझाव दिए गए। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि बैतूल जिले के चारों ओर रोड कनेक्टिविटी बेहतर है। यहां प्राकृतिक वन संपदा और संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। जिले में नवीन औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर लैंड बैंक बढ़ाया जाए। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर लैंड बैंक उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाए, जिससे बड़े उद्योगपति जिले में निवेश के लिए आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक भूमि संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के प्रयास किए जाएं।

जिले में दो नवीन औद्योगिक क्षेत्र एवं क्लस्टर हो रहे विकसित - महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बैतूल रोहित डावर ने बताया कि बैतूल जिले में औद्योगीकरण को बढावा देने एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दो नवीन औद्योगिक क्षेत्र एवं दो क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं जिनमें आगामी 5 वर्षों में लगभग 450 औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र, मोही 14.457 एकड़ भूमि पर स्थापित है। जिसमें प्रथम चरण में 6.213 हेक्टेयर भूमि पर लोक निर्माण विभाग एवं लघु उद्योग निगम द्वारा विकास कार्य प्रक्रियाधीन है। यहां आवंटन योग्य भू खण्डों की संख्या 34 है। आगामी दिसम्बर 2024 तक विकास कार्य पूर्ण कर भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। जिसमें आगामी वर्षों में लगभग 50 एमएसएमई को भूमि आवंटन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास के लिए 471.92 हेक्टेयर लैंड बैंक किया गया चिन्हित - महाप्रबंधक श्री डावर ने बताया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए हस्तांतरित 76 हेक्टेयर और आवंटन के लिए प्रक्रिया दिन 29 हेक्टेयर के अतिरिक्त औद्योगिक विकास के लिए 471.92 हेक्टेयर लैंड बैंक चिन्हित किया गया है। तहसील भैंसदेही के ग्राम धोंडी में 85.565 हेक्टेयर, तहसील भैंसदेही के ग्राम बडगांव में 22.921 हेक्टेयर, तहसील शाहपुर के ग्राम बाकाखोदरी में 14.657 हेक्टेयर और तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम सिवनी पाठ में 241.982 हेक्टेयर लैंड इस प्रकार कुल 471.92 हेक्टेयर लैंड बैंक चिन्हित किया गया है।

बाल विवाह व यौन उत्पीड़न अपराध : न्यायाधीश

● विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न

बैतूल। बाल विवाह व यौन उत्पीडऩ परिवार और समाज के अभिशाप है। इन कुरीतियों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी को आगे आकर शिक्षा के माध्यम से लोगों में जनजागृति लाकर इनके दुष्परिणाम बताने होंगे। जिससे इन पर रोक लग सके। यह बात शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय की न्यायाधीश दिव्यांगना जोशी व डॉ.महजबीन खान ने ढोंडवाड़ा स्कूल में आयोजित बाल विवाह, यौन उत्पीड़न व साइबर अपराध पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कही। कार्यशाला में इस संबंध में चित्रकला का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग विधिक समिति के अनेक राव गायकवाड़ व राजकुमार राठौर ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से बच्चों में करके सीखने के साथ आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए प्रतियोगिता के प्रभारी मदनलाल डढोरे ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को आज शनिवार जिला न्यायालय में आयोजित प्रदर्शनी में शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम प्रिया अनिल कुंभारे, द्वितीय तनीषा पाटनकर व तृतीय स्थान रूपाली पाटणकर ने प्राप्त किया। जिनको संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रीतिमाला माकोड़े, हेमलता चौधरी, योगेन्द्र मेहरा, मदनलाल डढोरे, कलावती हारोड़े, राजेन्द्र बेले, शारदा माथनकर, जाग्रति भावसार, अजीत बारंगे, जयदेव डोंगरे, नितीन पंवार, संदीप पांडे, सुभाष सातनकर, पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारी व ग्रामीण जन मौजूद थे।

हजारों महिलाओं ने दिया उदित सूर्य को अर्घ्य

● रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ छठ पूजा का समापन

बैतूल/सारणी। सतपुडा डेम के किनारे सजे छठ घाट पर गुरुवार की शाम एवं शुक्रवार की सुबह आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मौका था आस्था और विश्वास के लोक महापर्व छठ का। जहाँ हजारों की संख्या में महिलाओं ने शाम को अस्त होते एवं सुबह उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को सम्पन्न किया। भगवान भास्कर एवं छठी मईया के जयकारों से छठ घाट गूंज उठा। छठ पूजा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉ योगेश पण्डागरे एवं समापन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, नपा अध्यक्ष किशोर वरदे, एसडीओपी रोशन जैन, नपा उपाध्यक्ष जगदीश पवार, सीएमओ सीके मेश्राम विशेष रूप से मौजूद रहे। भोजपुरी एकता मंच की ओर से कमलेश सिंह, विककी सिंह, पीके सिंह एवं लक्ष्मण साहू ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम

● जीना इसी का नाम है का आयोजन रविवार को

देवास। शहर की सामाजिक संस्था एक्ट ईव फाउंडेशन अपने सामाजिक कामों की कड़ी में एक अभिनव कायक्रम का आयोजन करने जा रही है। जरुरतमंदों की सहायतार्थ होने वाले पुराने सदाबहार गीतों के लाईव शो जीना इसी का नाम है का आयोजन आगामी 10 नवंबर रविवार को किया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि इंदौर की सहयोगी संस्था सुमित्राज क्रिएशन के साथ आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में इंदौर के ख्यात गायक गायिका अपने सदाबहार सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में संगीत संयोजन हेमेंद्र महावर इंदौर का होगा । साथ ही इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को ट्रायसिकल भेंट की जायेगी और संगीत के माध्यम से विशेष गतिविधियां संचालित करने वाले अभिषेक गावड़े तथा सुमित्रा जोशी को सम्मानित किया जाएगा। मल्हार स्मृति मंदिर सभागार में रविवार 10 नवंबर की शाम 6.30 से होने वाले इस कार्यक्रम में सभी संगीतप्रेमी सादर आमंत्रित हैं।

भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम

देवास। भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला संघ देवास की विभिन्न संस्थाओं के स्काउट गाइड व स्काउटर गाइडर ने 7 नवंबर को स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया हेमेंद्र निगम काकू ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कमिश्नर स्काउट हरीसिंह भारतीय के निर्देशानुसार 7 नवंबर को शासकीय नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास में जिला मुख्य आयुक्त विष्णु वर्मा की अध्यक्षता में जिला कमिश्नर गाइड राजश्री काले, जिला कमिश्नर कब अशोक साहू के मुख्य अतिथि में जिला संघ उपाध्यक्ष एन के जोशी, संगीता वाटसन व पुष्पा भारती के विशेष आतिथ्य में हुआ । सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया तत्पश्चात सभी अतिथियों ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया । सभी अतिथियों का स्वागत स्काउट गाइड परंपरा अनुसार स्कार्फ वागल पहनकर किया आज के कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने क्रमशः अपने-अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात देवकरण सोलंकी के नेतृत्व में निबंध प्रतियोगिता, वंदना वर्मा के नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता, राजेश यादव के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान, किरण चौहान के नेतृत्व में प्रश्नोत्तरी का आयोजन, रिंकू कुशवाहा के नेतृत्व में स्वच्छता रैली और मंजू चौधरी के नेतृत्व में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई । डी ओ सी मनोज पटेल के

नेतृत्व में सभी वाहन रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता, एडिशनल कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, जिला कोषालय अधिकारी नेहा कलचुरी, जिला पंचायत कोषालय अधिकारी आशुतोष शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी हरिसिंह भारतीय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अजय सोलंकी, डाइट प्राचार्य अभय सिंह तौमर और नांदेड़ प्रचार्य दीपक शुक्ला, व्याख्याता प्रेम शर्मा को स्थापना दिवस के स्टीकर लगाकर सहयोग राशि एकत्रित की। तत्पश्चात हेमचंद आर्य के नेतृत्व में वाहन रैली नूतन विद्यालय पहुंची। इस अवसर पर जितेंद्र मंडलोई, शिवचरण लांगुरिया, देवकरण सोलंकी, हेमचंद्र आर्य, राजेश यादव, वंदना वर्मा, किरण चौहान, रिंकू कुशवाहा, मंजू चौधरी व मनोज पटेल जिला संगठन अधिकारी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव जितेंद्र मंडलोई ने किया व आभार शिवचरण अंगोरिया ने माना। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

चयनित शिक्षकों ने भाजपा ऑफिस के सामने बजाए थाली-कटोरे

महिलाएं बोलीं- 100 में से 90 नंबर लाने पर भी हम बेरोजगार, 20 हजार पद बढ़ाए जाएं

भोपाल (नप्र)। शिक्षक भर्ती (2023) वर्ग-1 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर थाली-कटोरे बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक रैली निकाली। पुलिस ने बीजेपी ऑफिस की तरफ जाने से रोका, तो महिलाओं ने रोड पर ही थाली-कटोरे बजाकर प्रदर्शन किया। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर अतिथि रख रहे अनुपमा ने आगे कहा कि जब आपके पास चयनित अभ्यर्थी हैं, जो टॉप-10 में आए हैं, तो उन्हें नियुक्ति न देकर आप अतिथि शिक्षकों को उन विषयों में जगह दे रहे हैं जबकि हमारे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 है, जिन्होंने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

6वें वेतनमान और निगम-मंडल के कर्मचारियों का डीए बढ़ा

● 1.40 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, 4 किस्तों में दिया जाएगा एरियर

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे लगभग 40 हजार और निगम-मंडल के 1 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 6वां वेतनमान प्राप्त करने वाले नियमित कर्मचारियों का डीए 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ 239 प्रतिशत हो गया है, जबकि निगम-मंडल के कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो बढ़कर 302 प्रतिशत हो गया है। इन कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 से दिया गया है। डीए का नगद लाभ अक्टूबर के वेतन से दिया जा रहा है। जबकि जनवरी से 30 सितंबर का एरियर 4 समान किस्तों में दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में दिया जाएगा।

पुरानी रंजिश को लेकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सुबह सवेरे सोहागपुर। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने वाले आरोपी महेंद्र उर्फ मोहनिया प्रजापति उम्र-46 वर्ष निवासी भोंखेडी कलां, थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम को धारा-302 भारतीय दंड विधान के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले की घटना का संक्षिप्त विवरण लोक अभियोजक वकील शंकरलाल मालवीय ने बताया कि घटना दिनांक 06 सितंबर 2021 को दोपहर करीब 01 बजे ललिताबाई कुशवाहा घर के अंदर कमरे में सो रही थी। तथा उसकी बहू प्रियंका घर पर काम कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी महेंद्र उर्फ मोहनिया प्रजापति अपने हाथ में तलवार लेकर घर के अंदर घुस आया। और पुरानी रंजिश को लेकर ललिता बाई कुशवाहा को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की नियत से तलवार से गले में, दाहिने हाथ में, पैरों में गंभीर चोट पहुंचायी। ललिता

बाई की बहू प्रियंका जान बचाकर घर से बाहर भाग गयी।हमला करने के बाद आरोपी तलवार लेकर वहां से भाग गया।थोड़ी देर बाद प्रियंका का जेठ डालचंद, छोटा भाई संतोष कुशवाहा और उसका पति मनोज कुशवाहा घर पर आए ।तब उनको घटना की सारी जानकारी दी। घायल ललिता बाई कुशवाहा को लेकर सोहागपुर थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई।ललिताबाई को घायल अवस्था में सोहागपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका प्राथमिक इलाज हुआ। बाद में उसे अग्रिम उपचार के लिए जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम भेजा गया। वहां इलाज के दौरान दिनांक 09 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गयी। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश सुरेशकुमार चौबे की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया जाने पर आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई ।शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक वकील शंकरलाल मालवीय ने प्रकरण में सशक्त पैरवी की थी।

भीख मांगकर अधिकारियों का पेट भरने एकत्रित राशि आबकारी के स्टाफ को भेंट की जाएगी : अखिलेश खंडेलवाल

नर्मदापुरम। पवित्र नगर की परिधि बनाकर पवित्र नगर की परिधि में बंद की गई शराब बिक्री का चलन नर्मदापुरम में गजब ढा रहा है। विधायक लिख रहे हैं नगर में खुले आम शराब बिक रही हैं, फिर पूर्व नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल शराब बिक्री रोकने को लेकर आन्दोलन कर रहे हस्ताक्षर अभियान चला रहे लेकिन शराब कारोबारियों से उपकृत हो रहा आबकारी विभाग मजाल बिक रही शराब कारोबार को रोक कर या बंद करके बता दें.. अब तो कुछ मामलों को अखबार में जगह देने पर घिन आने लगी, प्रशासन कितना भी लिख पढ़ लो गांधी जी के बंदरों वाली भूमिका निभा रहा हैं। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार तक में उससे नगर में बिक रही विधायक द्वारा दर्शाई दूकानों पर छापा मारने से परहेज़ रखा था अब मजेदार बात यह है कि नगर में चल रहे सप्त दिवसीय शिवलिंग निर्माण महोत्सव स्थल के सामने आज भी शराब बिक्री कारोबार यथावत है। ताज्जुब होता है शराब बेचने वालों को प्रशासन का तनिक भी भय नहीं, जबकि शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में कलेक्टर ने उपस्थित दर्ज कराते हुए भागीदारी की इतने सब-कुछ के बाद आबकारी विभाग ने अचानक नगर में देसी विदेशी शराब का जखीरा पकड़कर तो दिखा दिया लेकिन यह बता पाने से कतरा रही है कि अवैध शराब का यह जखीरा नर्मदापुरम नगर में किस शराब दुकान अथवा फैक्ट्री से निर्मित होकर सप्लाई हुआ ...? शराब बंदी के बाद कुटीर उद्योग में परिवर्तित शराब कारोबार अब घरों-घर सप्लाई हो रही है। नाबालिग, नौजवान इस कारोबार में लिप्त होकर भविष्य खराब कर रहे और प्रशासन तान कर सो रहा। फिलहाल तो नगर में पकड़ाई अवैध शराब के जखीरे को लेकर आबकारी विभाग जरुर प्रशासन के सामने अपनी सक्रियता साबित कर रहा उसके उल्ट शराब बिक्री को लेकर आन्दोलन कर रहे अखिलेश खंडेलवाल इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि ये कार्यवाही फॉर्मेलिटी है , मैं सारे आबकारी आमले के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा जितनी भी मौतें हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए फिर उन्होंने शराब के कारण हाल ही में फोर लेन पर हुई हत्या भी शराब के कारण बताया, इन सारे मामलों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को सह मुजरिम बनाने थाने में आवेदन के साथ होगा, मामला गंभीरतापूर्वक लेकर वे यह भी कह रहे हैं कि नगर में शराब बिक्री रोकने में असमर्थ विभाग के लिए भीख मांगकर ऐसे अधिकारियों का पेट भरने हेतु राशि एकत्रित कर आबकारी के स्टाफ को भेंट की जाएगी ।

मध्यप्रदेश को वेलनेस और मेडिकल हब बनाने की पहल 'हृदयम एमपी' का शुभारंभ

● 'हृदयम एमपी' पहल प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म के इको सिस्टम को विकसित करने का प्रयास : प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ● प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में हब बनाने का लिया संकल्प ● 'हृदयम एमपी' का लोगो हुआ लॉन्च

भोपाल (नप्र)। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि 'हृदयम एमपी' पहल प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म के इको सिस्टम को विकसित करने का प्रयास करेगी। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित होगा जिस पर पर्यटन और वेलनेस और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के सभी स्टेक होल्डर्स समन्वित रूप से कार्य करेंगे। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में 'हृदयम एमपी' पहल के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेडिकल और वेलनेस चिकित्सा पद्धति के सभी संसाधनों को एकीकृत करते हुए प्रदेश में पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित करने के लिए 'हृदयम एमपी' पहल कार्य करेगी। इस अवसर पर 'हृदयम एमपी' का लोगो भी लॉन्च किया गया। एमपी टूरिज्म द्वारा फिक्की के सहयोग से वेलनेस और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पर आधारित कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया था।

आयुक्त आयुष सुश्री सलोनी सिडाना ने कहा कि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कैफेटेरिया एप्रोच का जिक्र किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा में इंटीग्रेटेड एप्रोच को विकसित किया गया। प्रदेश में आयुष के तहत यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी सहित सभी पद्धति की चिकित्सा प्रदान की जा रही है। वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म के लिए मध्यप्रदेश उपयुक्त हैं।

फिक्की के आयुष कमेटी के चेयरमैन और श्री श्री तत्व के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद वर्चस्वी,

कैरियर ग्रुप के चेयरमैन श्री मनीष राजोरिया, फिक्की के वेलनेस टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन और आयुर्वेद माना हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री संजीव कुरूप, चिरायु ग्रुप के संस्थापक श्री अजय गोयनका ने प्रदेश में वेलनेस व मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की संभावनाओं पर बात कही। आयोजन में मंचासीन अतिथियों के साथ ही आयुष व आयुर्वेद चिकित्सक, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी, होटेलियर, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, पर्यटन और आयुष विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

हृदयम एमपी पहल के तहत, राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति निर्धारण कर शासन स्तर पर प्रोत्साहन देना, लैंड बैंक तैयार करना इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगलों, पहाड़ों और जल स्त्रोतों का लाभ उठाकर ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जो पर्यटकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखे।

फिक्की के आयुष कमेटी के चेयरमैन और श्री श्री तत्व के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद वर्चस्वी ने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद और वेलनेस के प्रति रुझान बढ़ा है। यह सभी चिकित्सा देश में पुरातन काल से उपलब्ध है। इसके साथ ही इन चिकित्सा पद्धति का उचित मूल्य भी विदेश के लोगों को आकर्षित करता है।

कैरियर ग्रुप के चेयरमैन श्री मनीष राजोरिया ने कहा कि यूरोप, यूके और अमेरिका सहित अन्य देशों से भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहें हैं। उसका एक प्रमुख कारण सस्ता इलाज हैं। डेंटल इंप्लांट, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रॉमा, पोस्ट रेडियो थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट कम दाम में प्रदेश में उपलब्ध है। साथ ही प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। इस कारण प्रदेश मेडिकल टूरिज्म के लिए उपयुक्त है।

सोनकच्छ जनपद पंचायतों में पानी बचाने को लेकर हो रहा उल्लेखनीय काम

देवास। देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देवास शहर में मात्र 100 दिनों में 225 करोड़ लीटर वर्षा का जल बचाने के साथ ही जिलेभर में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु प्रजापति के निर्देशानुसार देवास जिले में जल संचय की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से क्या और कैसा काम हुआ है ये जानने के लिए अमृत संचय अभियान में जुड़ी टीमें जिले की अलग अलग जनपदों का निरीक्षण करके सरपंचों से सार्थक संवाद कर रही है।

अमृत संचय अभियान के तहत सोनकच्छ जनपद में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें जनपद पंचायतों के 30 से अधिक सरपंच उपस्थित थे। जनपद सीईओ श्री चरक शिवहरे की उपस्थिति में अमृत संचय टीम के श्री मोहन वर्मा, श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री महेश सोनी तथा श्रीमती शर्मीला ठाकुर से सभी सरपंचों ने अपने-अपने गाँव की स्थिति और काम की जानकारी साझा की।

जनपद सीईओ श्री चरक शिवहरे ने बताया कि जनपद की 66 पंचायतों में 198 शासकीय भवनों सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी, पंचायत भवनों में जनभागीदारी से रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए है। साथ ही 101 बोरी बन्धान के लक्ष्य के सामने 117 बोरी बन्धन का काम किये गये है। जनपद क्षेत्र में 343 निजी भवन स्वामियों ने भी रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए है।

बैठक में जहां अमृत संचय टीम के श्री मोहन वर्मा ने उपस्थित सरपंचों से जल संचय और पानी की बचत के बारे में विस्तार से चर्चा की वहीं खेरिया जागीर के महेन्द्र सिंह चौहान, धतुरिया राम के महिपाल सिंह गुर्जर, गंधर्वपुरी के मुकेश भाई, जोलाय के लखनसिंह देवड़ा, कुमारिया जागीर के छोटे लाल जाधव ने क्षेत्र में हुए कामों की जानकारी साझा की और सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री आवास के मकानों पर भी रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया जाये। इस दौरान श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री महेश सोनी तथा श्रीमती शर्मिला ठाकुर ने भी संबोधित किया।

विधान सभा उपचुनाव प्रचार

जाति का गणित तय करेगी विजयपुर की जीत, मुख्यमंत्री पहुंचे आदिवासियों के बीच, कांग्रेस ने पायलट को उतारा

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस का गढ़ रही श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। 6 बार कांग्रेस से जीत चुके रामनिवास रावत अब वन मंत्री के रूप में भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उनके सामने सहरिया आदिवासी समुदाय के मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। ढाई लाख मतदाताओं में से सर्वाधिक 70 हजार इसी समुदाय के हैं। पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर भी मल्होत्रा 48 हजार वोट ले गए थे। इस सीट पर आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा समुदाय रावत-मीणा है। इनकी संख्या लगभग 20 हजार है। रामनिवास रावत इसी समाज के हैं। यहां लगभग 10 हजार गुर्जर मतदाता हैं।

वीडी शर्मा ने कहा- कांग्रेस आदिवासियों का हक छीनती आई

- मुख्यमंत्री ने आदिवासी इलाके में प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य नेताओं के साथ आदिवासी इलाकों में सभाएं और रोड शो किए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस यहां डाकू-लुटेरों के दम पर जीतती थी, भाजपा ने सत्ता में आते ही डाकुओं का सफाया किया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गरीब आदिवासियों का हक छीनती आई है, लेकिन भाजपा उनकी भलाई के काम करती है।

पटवारी ने कहा- रावत ने जनता से विश्वासघात किया - कांग्रेस ने गुर्जर वोट को साधने के लिए राजस्थान के गुर्जर नेता सचिन पायलट को मैदान में उतार दिया है। पायलट ने गुरुवार को यहां आमसभा की। पायलट ने कहा - पूरे मप्र में माफियाराज फैला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने कांग्रेस और जनता दोनों से विश्वासघात किया। उधर, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर कहा कि कांग्रेस का स्टैंड साफ है। जनमत का सम्मान होना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के नये मुकाम पर मध्यप्रदेश

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव

द्वारा

सिंगल क्लिक से अंतरण

₹ 1573 करोड़

1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को

₹ 55 करोड़

सिलेंडर रीफिल के लिए
26 लाख बहनों को

₹ 333 करोड़

55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन
हितग्राहियों को

9 नवम्बर, 2024 । अपराह्न 4:00 बजे । इंदौर, मध्यप्रदेश

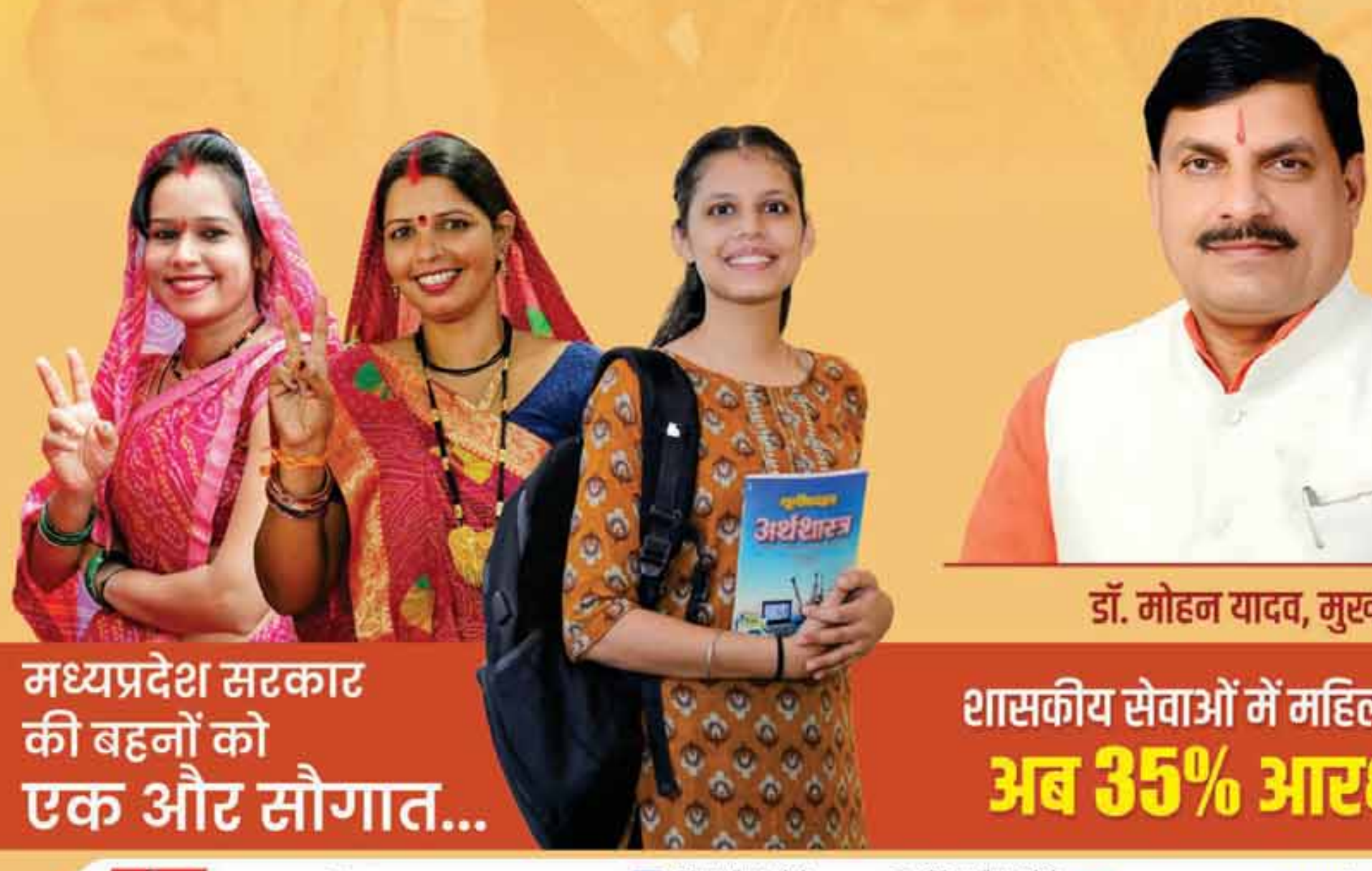

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश सरकार
की बहनों को
एक और सौगात...

शासकीय सेवाओं में महिलाओं को
अब 35% आरक्षण

D-11097/24

सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP #MPKiLadliBehna